घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 261- बुधवार 22- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

नीट मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का धरना

राहुल गांधी का बड़ा बयान....बोले-शिक्षा व्यवस्था टूट चुकी,पीएम मोदी छात्रों से मांगें माफी

नई दिल्ली,21 जुलाई 2026। पीएम आवास के पास मंगलवार दोपहर साढ़े तीन बजे धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस शाम साढ़े 6 बजे उठाकर ले गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी,मल्लिकार्जुन खड़गे,अखिलेश यादव समेत कई नेता को हिरासत में ले लिया है। सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल से 2 बार बातचीत की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे तो कांग्रेसियों ने घेरा बना लिया और राहुल तक पहुंचने नहीं दिया। कांग्रेसियों और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का-मुक्की होती रही। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले गए और बस में बैठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है और उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने और आंदोलन कर रहे छात्रों पर हो रही पुलिस कार्रवाई रोकने की मांग की।

शिक्षा व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है...

राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश को पता है कि शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। उनके अनुसार,छात्रों की शिकायतें पूरी तरह जायज हैं और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस विषय पर सरकार के सामने कई बार अपनी बात और सुझाव भी रखे हैं। इसके बावजूद छात्रों की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया।

जितेंद्र सिंह और राहुल के बीच 20 मिनट बात

पीएम आवास के पास से हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन पहुंचे थे। राहुल गांधी से करीब 20 मिनट बात की। इसके बाद जितेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह के पास गए। शाह से बातचीत के बाद उन्होंने फिर राहुल से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि NEET पर संसद में चर्चा हो। राहुल की यह मांग मान ली गई थी। लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए। वह बोले- अब हमारी दो मांगे हैं। पहली- नीट पर संसद में चर्चा,दूसरी शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा।

सोनम वांगचुक को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भेजा गया

पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम यहां के सफदरजंग अस्पताल ने छुट्टी दे दी। उन्हें आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल की चिकित्सकीय टीम को सौंप दिया गया है। सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार शाम 6:40 बजे सोनम वांगचुक को आगे के इलाज के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल की चिकित्सकीय टीम को सौंप दिया गया। बुलेटिन के मुताबिक छुट्टी के समय उनके आवश्यक स्वास्थ्य मानक स्थिर थे। हालांकि, पैनसाइटोपेनिया (रक्त की तीनों प्रमुख कोशिकाओं–लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स–की कमी) की स्थिति बनी हुई है।

जितेंद्र सिंह बोले...नीट पर चर्चा की मांग मानी,लेकिन अब मुकरे

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पोस्ट करके कहा- राहुल की मांग थी कि संसद में नीट पर चर्चा हो। सरकार ने उनकी बात मान ली तो वह अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा- अब हमारी दो मांगे हैं। नीट पर चर्चा के साथ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए।

राहुल ने कहा- पीएम अब बच नहीं सकते : राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देश भक्त भारतीय से अपील करता हूं, जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हों।

नीट-यूजी मुद्दे पर संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा,छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली,21 जुलाई 2026। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों में मंगलवार को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा जारी रखा जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित होने के बाद बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। लोकसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा जिसके कारण कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। लोकसभा की कार्यवाही दो बजे फिर शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने और अपने-अपने स्थान पर बैठने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियम 377 के तहत सदस्यों को जनहित के मुद्दे सदन के पटल पर रखने दिया जाए। इसके लिए करीब 20 मिनट का समय भी दिया गया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। पीठासीन अधिकारी ने कई बार शांति बनाए रखने और सदन चलने देने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा नहीं थमा। कार्यवाही जब 02 बजे फिर शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों से कार्यसूची के अनुसार सदन चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के लिए निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए और जो सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं, वे क्रमवार बोलें। उन्होंने सभी सदस्यों से शोर-शराबा नहीं करने और सदन की कार्यवाही में सहयोग देने की अपील की। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति ने कार्यवाही शुरू होने के लगभग एक मिनट बाद ही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री ने देश के लाखों छात्रों को आश्वस्त करते हुए साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा और पेपर लीक के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में हुई अहम चर्चाओं की विस्तार से जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई।

नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री ने सख्ती, कड़ी सजा और भविष्य के लिए एक 'फुलप्रूफ सिस्टम' तैयार करने की बात पर विशेष जोर दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील और सतर्क है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार की तत्परता का जिक्र करते हुए बताया गया कि मामले में री-एग्जाम भी सफलतापूर्वक कराया गया और रिजल्ट जारी करने में भी कोई देरी नहीं होने दी गई। नीट विवाद पर विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पकड़े गए आरोपियों को हर हाल में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी को नसीहत देते हुए कहा कि यह सिर्फ किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं और उनके भविष्य से जुड़ा मामला है। इसलिए इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बिल्कुल भी दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलकर समाधान की दिशा में काम करना चाहिए।

पंजाब-हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला वापस लिया,गिरफ्तार किसान होंगे रिहा

चंडीगढ़,21 जुलाई 2026। प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर जुटे किसानों ने फिलहाल आंदोलन को स्थगित करते हुए वापस लौटने का फैसला लिया है। शंभू व खनौरी बॉर्डर से किसान अपने घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं। दिनभर बॉर्डर पर चले हंगामे के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ हुई बैठक में दो मुख्य मांगों पर सहमति के बाद किसान संगठनों ने धरना खत्म करने का फैसला लिया। शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसान नेताओं से मुलाकात की। बैठक के दौरान किसानों की दो प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। कृषि मंत्री ने किसान प्रतिनिधियों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत करवाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही हिरासत में लिए गए किसान नेताओं और अन्य किसानों को रिहा करने का भरोसा भी दिया गया। किसान नेताओं के अनुसार सरकार ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच अगले एक सप्ताह के भीतर वार्ता करवाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद किसान संगठनों ने अपना धरना समाप्त करने और शंभू बॉर्डर खाली करने का फैसला लिया।

मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित

भोपाल,21 जुलाई 2026। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड- यूसीसी) विधेयक पारित हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक, हंगामा और नारेबाजी हुई। विपक्ष के तीखे विरोध और वॉकआउट के प्रयासों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही जारी रखते हुए विधेयक को पास घोषित कर दिया। विधानसभा में आज मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया। सदन में प्रस्ताव रखते ही विपक्ष हमलावर हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे विस्तृत समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। हालांकि,सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई। मांग नहीं माने जाने पर कांग्रेस विधायक विरोध जताते हुए सदन के बीचो-बीच पहुंच गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। वहीं भाजपा विधायक और मंत्री विधेयक पर तुरंत चर्चा कराकर इसे पास कराने पर अड़े रहे। सदन में बढ़ते हंगामे और अव्यवस्था को देखते हुए अध्यक्ष तोमर ने कार्यवाही को पहले 10 मिनट और फिर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने इस बिल को सत्ता पक्ष का राजनीतिक एजेंडा करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने संविधान के अनुच्छेद 29 का हवाला देते हुए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक सीताराम शर्मा ने यूसीसी पर संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को सिर पर लेकर घूमती है, संविधान मानने की बात करती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश को नहीं मानती है। कांग्रेस के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो हिंदू की बात करेगा,वही राज करेगा। उन्होंने कहा कि समानता हमारी संस्कृति का मूल है।

संपादकीय

फुटबॉल के उतार-चढ़ाव

आखिरकार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में स्पेन के हाथों पिछले चैंपियन अर्जेंटीना की हार के साथ ही दुनियाभर में छाया फुटबॉल का खुमार थम गया। निस्संदेह, यह फुटबॉल के इतिहास का सबसे बड़ा विश्वकप था। संभवतः हाल के दशकों में संपन्न विश्वकप मुकाबलों में सबसे अधिक विवादास्पद भी। इस आयोजन को सफल बनाने में तीन मेजबान देशों-अमेरिका,कनाडा और मैक्सिको की भागीदारी रही है। इस टूर्नामेंट में 48 टीमों ने शिरकत की और 104 मैचों का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता को तो दिखाया ही,साथ ही इस खेल के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए। बहरहाल,स्पेन ने 16 साल बाद अपना यह दूसरा खिताब जीता। उसने एक औसत दर्जे के फाइनल मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। वहीं दूसरी ओर तीसरे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला टूर्नामेंट की दो सबसे शानदार टीमों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। इस बेहद रोमांचक और यादगार मुकाबले में इंग्लैंड ने 6-4 से जीत हासिल की। वहीं इस टूर्नामेंट में कुछ अल्प ज्ञात टीमों का प्रदर्शन फुटबॉल की दुनिया में उम्मीद जगाने वाला रहा। इस विश्व कप में कैप वर्डे,डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और कुराकाओ जैसे छोटे देशों का प्रेरणादायक खेल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। बहरहाल,एक बार फिर किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी जैसे फुटबॉल के बड़े सितारों ने इस सबसे बड़े मंच पर अपनी चमक बिखेरी। दूसरी ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक बार फिर कहानी निराशाजनक रही। उनके प्रशंसक उनकी यादगार विदाई चाहते थे। लेकिन किसी भी खिलाड़ी की कामयाबी में टीम वर्क की बड़ी भूमिका होती है। खिलाड़ियों की साझी भूमिका से ही बड़े स्टार खिलाड़ी चमक सकते हैं। यही वजह है कि किलियन एम्बाप्पे और लियोनेल मेसी जैसे अद्भुत खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद विश्वकप खिताब से वंचित रह गए।

निस्संदेह,किसी भी मजबूत टीम के नगीनों के साझे प्रयास से ही स्वर्णिम सफलता का निर्धारण हो पाता है। बहरहाल,अब तक के सबसे बड़े और तीन देशों में खेले गए इस टूर्नामेंट के साथ कई तरह के विवाद भी जुड़े। टेक्नोलॉजी पर फीफा की बढ़ती निर्भरता को लेकर भी आलोचकों ने सवाल उठाये। विशेष रूप से वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी वीएआर सिस्टम को लेकर संशय पैदा हुआ। फुटबॉल प्रेमियों ने माना कि यह सिस्टम भरोसेमंद नहीं है। इसके उपयोग और भूमिका को लेकर कई खिलाड़ियों,कोचों और दर्शकों में नाराजगी देखी गई। वहीं दूसरी ओर अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक को लेकर भी काफी हंगामा देखने में आया। दरअसल, ये अमेरिकी खेलों में होने वाले टैक्टिकल टाइमआउट जैसे थे। फुटबॉल प्रेमियों का आरोप था कि इससे खेल की लय टूटी है। दूसरी तरफ कमर्शियल मौके बनते देखे गए। यह पहले से तय था कि अनावश्यक दखलंदाजी के लिये चर्चित अमेरिकी राष्ट्रपति का दखल भी इस टूर्नामेंट में दिखेगा। क्योंकि इस आयोजन के मुख्य टूर्नामेंट अमेरिका में खेले जा रहे थे। इस आयोजन के दौरान तब विवाद सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो से अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को दिखाए गए रेड कार्ड की समीक्षा करने को कहा था। विवाद तब उठना शुरू हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दखल के बाद अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन पर से एक मैच का बैन हटा लिया गया, जिसके बाद बालोगुन ने राउंड-ऑफ-16 का मैच खेला। लेकिन इस अभूतपूर्व दखल के बाद दंभी अमेरिका टूर्नामेंट से बाहर होने से नहीं बच पाया। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप फीफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो के साथ पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होने के लिये मैदान पर आए तो लोगों ने अपनी भड़ास निकालते हुए खूब हूटिंग की। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस आयोजन के दौरान जो खामियां सामने आई,आने वाले विश्वकप में फीफा उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा।

चंद्रशेखर आजाद-भारत का वह पुत्र, जिसने सिर झुकना सीखा ही नहीं

स्वतंत्रता का सबसे निर्भीक हस्ताक्षर-चंद्रशेखर आजाद

कृति आरके जैन
बड़वानी (मप्र)

कभी-कभी इतिहास राजाओं के मुकुट से नहीं,एक साधारण युवक की भींची हुई मुट्ठी से बदलता है। साम्राज्य हमेशा तोपों से नहीं टूटते,वे अडिग संकल्प के सामने भी ढह जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसा ही एक संकल्प जन्मा था–चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने केवल अंग्रेजी सत्ता को चुनौती नहीं दी, बल्कि भारतीयों के मन में जड़ जमा चुके भय और मानसिक गुलामी पर भी प्रहार किया। वे जानते थे कि जिस दिन भारतीय का भय टूट जाएगा,उसी दिन साम्राज्यवाद की नींव भी हिल जाएगी। इसलिए उनका संघर्ष केवल हथियारों का नहीं,बल्कि आत्मसम्मान,स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के जागरण का था। 23 जुलाई 1906 को तत्कालीन अलिराजपुर रियासत (वर्तमान मध्यप्रदेश) के भाबरा गांव में जन्मा वह बालक किसी राजमहल का वारिस नहीं था। न उसके पास धन था,न सत्ता,न सेना; पर उसके भीतर ऐसा स्वाभिमान था,जो किसी भी साम्राज्य से विशाल था। इतिहास साक्षी है कि जब किसी राष्ट्र की मिट्टी ऐसे सपूतों को जन्म देती है,तब गुलामी की उम्र सिमटने लगती है। जलियांवाला बाग का रक्तपात केवल निर्दोषों की हत्या नहीं था,वह एक पूरी पीढ़ी के हृदय में प्रतिकार की ज्वाला बनकर धधक उठा। उसी ज्वाला ने चंद्रशेखर के मन में ऐसा अटूट संकल्प जगाया,जिसे कोई शक्ति डिगा न सकी। उन्होंने समझ लिया था कि अन्याय अपने आप समाप्त नहीं होता;उसे साहस,त्याग और मृत्यु से भी बड़े संकल्प से परास्त करना पड़ता है।

किशोर अवस्था में 1921 में जब उन्हें अंग्रेजी अदालत में पेश किया गया और नाम पूछा गया,तो उन्होंने कहा –'आजाद'। पिता का नाम 'स्वतंत्रता' और गांव का नाम 'जेल' बताया। यह उत्तर केवल परिचय नहीं,बल्कि दासता के चेहरे पर करारा प्रहार और पूरे राष्ट्र के स्वाभिमान की उद्घोषणा था। अदालत में खड़ा वह किशोर अभियुक्त नहीं,स्वतंत्र भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था। उनका जीवन सिद्ध करता है कि क्रांति केवल हथियार उठाने से नहीं,भय को पराजित करने से जन्म लेती है। जिस मनुष्य के भीतर भय समाप्त हो जाए,उसे संसार की कोई शक्ति झुका नहीं सकती। यही कारण था कि अंग्रेजी शासन उनके शरीर को तो घेर सका, पर उनके अदम्य आत्मबल को कभी बंदी नहीं बना सका। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को केवल संगठन नहीं,अटूट विश्वास दिया। उन्होंने सिखाया कि राष्ट्र का निर्माण नारों से नहीं, त्याग और समर्पण से होता है। उन्होंने अपने लिए कभी घर नहीं बसाया, क्योंकि पूरा भारत ही उनका घर था। उन्होंने अपने भविष्य से अधिक राष्ट्र के भविष्य को चुना। उनका सबसे बड़ा शस्त्र उनका चरित्र था। वे जानते थे कि अनुशासन के बिना संघर्ष सफल नहीं होता, नैतिकता के बिना क्रांति टिकती नहीं और संगठन के बिना बलिदान इतिहास नहीं रचता। इसलिए उनका जीवन अनुशासन, त्याग और राष्ट्रसमर्पण का पर्याय बन गया। उनका प्रत्येक क्षण राष्ट्र की अमानत था। आज जब हम स्वतंत्र भारत में साँस लेते हैं, तब यह प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए–क्या हम वास्तव में उतने ही स्वतंत्र हैं,जितना हमारे पूर्वज हमें बनाना चाहते थे? यदि समाज भ्रष्टाचार से समझौता कर ले,यदि युवा सुविधा को संघर्ष से बड़ा मानने लगे,यदि राष्ट्रहित से पहले स्वार्थ खड़ा हो जाए,तो क्या केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त है? चंद्रशेखर आजाद आज भी इसी प्रश्न का उत्तर बनकर हमारे सामने खड़े हैं। उनका जीवन कहता है कि पराधीनता केवल विदेशी शासन नहीं होती।

राम मंदिर विवाद की आंच के बीच बीजेपी का 2027 मिशन,बूथ से चुनावी शंखनाद

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के हालिया उत्तर प्रदेश दौरे के बाद पार्टी के इस संगठनात्मक अभियान को और गति मिली है। जुलाई की शुरुआत में लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नबीन ने राम मंदिर चढ़ावे के विवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला था। उन्होंने कांग्रेस,समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों पर धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर,अखिलेश यादव ने नितिन नबीन के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर राजनीतिक तंज किया। इस तरह विवाद का राजनीतिक असर साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन बीजेपी अब इस मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति का स्थायी केंद्र नहीं बनाना चाहती। पार्टी को पता है कि अगर चुनावी राजनीति लगातार आरोप-प्रत्यारोप के इर्द-गिर्द घूमती रही तो संगठनात्मक तैयारी पीछे छूट सकती है। यही वजह है कि पार्टी ने राजनीतिक नैरेटिव को विवाद से संगठन की ओर मोड़ने की कोशिश शुरू की है। संदेश यह है कि जांच और राजनीतिक बहस अपनी जगह चलती रहेगी,लेकिन चुनावी तैयारी रुकने वाली नहीं है…

अजय कुमार
लखनऊ (उ. प्र.)

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा रखा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार और बीजेपी को घेरने की तैयारी में है, जांच की दिशा और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है,जबकि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम गठित करने का फैसला किया है। राजनीतिक रूप से यह विवाद बीजेपी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन पार्टी ने इस पूरे माहौल का जवाब किसी नए राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से देने के बजाय अपना ध्यान सीधे संगठन पर केंद्रित करने का फैसला किया है। बीजेपी अब राम मंदिर चढ़ावा विवाद की राजनीतिक गर्मी से आगे निकलकर 2027 के विधानसभा चुनाव की असली जमीन तैयार करने में जुट गई है बूथ।22 जुलाई को उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में एक साथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर पार्टी अपने बूथ नेटवर्क को एक साथ परखने जा रही है। बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में करीब 1.62 लाख बूथ अध्यक्ष हैं। इन्हीं बूथों को पार्टी अपनी चुनावी मशीनरी की सबसे निचली,लेकिन सबसे निर्णायक इकाई मानती है। सम्मेलन में केवल भाषण नहीं होंगे,बल्कि बूथ अध्यक्षों की मौजूदगी, उनके कामकाज और चुनावी तैयारियों का वास्तविक परीक्षण किया जाएगा। यानी 22 जुलाई को बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटा रही है,बल्कि अपने संगठन की जमीनी हालत का हिसाब लेने जा रही है। पार्टी ने बूथ अध्यक्षों को उनके बूथ नंबर के हिसाब से बैठाने की व्यवस्था की है। कुर्सियों पर नाम की जगह बूथ नंबर दर्ज होगा। मंच से किसी भी बूथ अध्यक्ष को अचानक बुलाया जा सकता है और उससे उसके बूथ से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। पार्टी यह जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति के हाथ में बूथ की जिम्मेदारी है, क्या वह वास्तव में अपने इलाके के मतदाताओं,कार्यकर्ताओं और चुनावी समीकरण से परिचित है। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन बीजेपी की तैयारी चुनावी साल के इंतजार पर निर्भर नहीं रहना चाहती। पार्टी की रणनीति साफ है पहले बूथ को मजबूत करो, फिर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रणनीति तैयार करो। जहां बूथ अध्यक्ष सक्रिय हैं, वहां संगठन को और मजबूत किया जाएगा। जहां निष्क्रियता या कमजोरी मिलेगी,वहां सुधार,जिम्मेदारी में बदलाव या नए कार्यकर्ताओं को आगे लाने पर विचार किया जा सकता है।

22 जुलाई के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों से संवाद करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी सीतापुर के लहरपुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बरेली शहर और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा में बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वाराणसी में रहेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और स्वतंत्र देव सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं को भी अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। यह व्यवस्था अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व यह दिखाना चाहता है कि 2027 का चुनाव केवल मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं होगा। मंत्री,विधायक,संगठन पदाधिकारी और बूथ अध्यक्ष सभी को एक ही चुनावी ढांचे में काम करना होगा।

पार्टी ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को भी कार्यक्रम में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संगठन अब चुनावी तैयारी को पूरी तरह सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है। इस अभियान का दूसरा बड़ा हिस्सा बीजेपी का डेटा आधारित संगठन है। पार्टी ने सदस्यता अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाए थे। अब इन सदस्यों की जानकारी को बूथ और मंडल स्तर पर व्यवस्थित करने की कोशिश हो रही है। इसका उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि पार्टी के कितने सदस्य हैं,बल्कि यह पता लगाना है कि इनमें से कितने लोग वास्तव में सक्रिय हैं और चुनाव के समय पार्टी के लिए काम कर सकते हैं।

यही बदलाव बीजेपी की चुनावी रणनीति को पहले के मुकाबले अधिक संगठित बनाता है। किसी बूथ पर कितने कार्यकर्ता सक्रिय हैं,किन इलाकों में पार्टी की पकड़ कमजोर है,किस सामाजिक समूह तक संगठन की पहुंच कम है और किन मतदाताओं से नियमित संपर्क नहीं हो रहा इन सवालों का जवाब डेटा और जमीनी सत्यापन के जरिए खोजा जाएगा। 1.62 लाख बूथ अध्यक्षों की सक्रियता का आकलन इसी बड़ी योजना का हिस्सा है।राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने बीजेपी को राजनीतिक रूप से रक्षात्मक स्थिति में डालने की कोशिश जरूर की है। विपक्ष इस मुद्दे को विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में भी उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच से जुड़े सवालों ने भी मामले को और गंभीर बना दिया है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे मंदिर से जुड़े विवाद पर राजनीतिक और कानूनी सवालों का सामना करना है,दूसरी तरफ उसे 2027 की चुनावी मशीनरी को कमजोर नहीं पड़ने देना है। यही कारण है कि 22 जुलाई का सम्मेलन बीजेपी के लिए महज संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं है। यह एक तरह से पार्टी का पहला बड़ा जमीनी ऑडिट है। मंच पर मुख्यमंत्री और बड़े नेता होंगे, लेकिन असली परीक्षा उन बूथ अध्यक्षों की होगी जो चुनाव के दिन पार्टी की पूरी रणनीति को जमीन पर उतारते हैं। मतदाता सूची से लेकर घर-घर संपर्क तक, लाभार्थियों से संवाद से लेकर मतदान के दिन की व्यवस्था तक,बूथ अध्यक्ष की भूमिका चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालती है।उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 403 विधानसभा सीटें हैं और हर क्षेत्र में अलग सामाजिक और राजनीतिक समीकरण हैं,वहां किसी भी पार्टी के लिए एक समान रणनीति काम नहीं कर सकती। बीजेपी अब इसी स्थानीय अंतर को समझने के लिए बूथ स्तर तक पहुंचना चाहती है। पार्टी के लिए चुनौती यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश तेज की है। समाजवादी पार्टी का पीडीए सामाजिक समीकरण और कांग्रेस की संगठन विस्तार की कोशिश बीजेपी के सामने अलग-अलग राजनीतिक चुनौतियां खड़ी करती हैं। ऐसे में बीजेपी की रणनीति का केंद्र एक बार फिर वही पुराना लेकिन प्रभावी मॉडल है बड़ा नेता ऊपर, मजबूत संगठन नीचे और चुनावी तैयारी लंबे समय तक। फर्क इतना है कि इस बार पार्टी बूथ अध्यक्षों की मौजूदगी और सक्रियता को केवल संगठनात्मक रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहती। वह उन्हें सामने बैठाकर परखना चाहती है।22 जुलाई को 403 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाला यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से यह तय होगा कि बीजेपी का संगठन कागज पर कितना बड़ा है और जमीन पर कितना सक्रिय। राम मंदिर विवाद की राजनीतिक आंच के बीच बीजेपी ने अपना जवाब तैयार कर लिया है। पार्टी का संदेश साफ है विवादों का सामना राजनीतिक स्तर पर किया जाएगा, लेकिन चुनावी तैयारी बूथ से शुरू होगी। 2027 की लड़ाई अभी दूर है, मगर बीजेपी ने अपने सबसे छोटे संगठनात्मक कार्यकर्ता को मैदान में उतारकर यह संकेत दे दिया है कि उसके लिए चुनाव का असली काउंटडाउन शुरू हो चुका है।

वैश्विक युद्ध की प्रबल संभावना,शांति की बात अब कोरी कल्पना

संजीव ठाकुर
रायपुर छत्तीसगढ़

अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल की हठधर्मिता ईरान के प्रमुख की हत्या का बदला लेने की सनक ने वैश्विक शांति को तार तार कर दिया है। अब वैश्विक शांति तथा शांति वार्ता की बातों को परी कल्पना ही मानकर चलिए,शांति की बात अब दूर की कौड़ी होती दिखाई दे रही है। सभ्यता ने विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, किंतु विडंबना यह है कि इसी सभ्यता का नेतृत्व करने वाले अनेक विश्व नेता आज भी युद्ध, हथियारों की होड़ और शक्ति प्रदर्शन की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा संकट केवल आर्थिक असमानता या पर्यावरणीय विनाश नहीं,बल्कि वह मानसिक अस्थिरता और वैचारिक भ्रम है जिसने वैश्विक नेतृत्व को असंवेदनहीन बना दिया है। शांति की भाषा आज उन्हें कमजोरों की भाषा प्रतीत होती है, जबकि इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास केवल शांति और सहअस्तित्व से ही संभव हुआ है। आज दुनिया के कई शक्तिशाली राष्ट्र युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध,मध्य-पूर्व में इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष,चीन-ताइवान तनाव, उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियाँ और आतंकवाद की बढ़ती घटनाएँ यह प्रमाणित करती हैं कि विश्व नेतृत्व संवाद के स्थान पर टकराव को प्राथमिकता दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मानवता की करुणा पर सत्ता की महत्वाकांक्षा भारी पड़ गई हो। महात्मा गांधी ने कहा था आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। गांधीजी का यह कथन आज पहले से अधिक प्रासंगिक दिखाई देता है। विश्व के बड़े नेता प्रतिशोध और प्रभुत्व की राजनीति में इतने उलझ चुके हैं कि उन्हें युद्ध के पीछे रोती मानवता दिखाई नहीं देती। लाखों निर्दोष नागरिक विस्थापित हो रहे हैं,बच्चे अनाथ हो रहे हैं,अर्थव्यवस्थाएँ बिखर रही हैं,किंतु हथियार उद्योग और सामरिक राजनीति लगातार फल-फूल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था हमें युद्ध को मानवता के भविष्य से बाहर करना होगा। दुर्भाग्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएँ भी आज महाशक्तियों के राजनीतिक दबाव से पूर्णतःस्वतंत्र नहीं रह पाई हैं। वीटो शक्ति रखने वाले देश अक्सर अपने हितों के अनुसार वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप शांति वार्ताएँ केवल औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। विश्व के बड़े नेताओं की मानसिकता में एक गहरा भय भी दिखाई देता है–सत्ता खोने का भय,वर्चस्व समाप्त होने का भय और दूसरे राष्ट्र के अधिक शक्तिशाली हो जाने का भय। यही भय उन्हें शांति की जगह युद्ध की तैयारी की ओर धकेलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ.केनेडी ने अपने एक ऐतिहासिक भाषण में कहा था मानव जाति को युद्ध समाप्त करना होगा,अन्यथा युद्ध मानव जाति को समाप्त कर देगा। केनेडी की यह चेतावनी आज परमाणु हथियारों से लैस दुनिया के लिए किसी भविष्यवाणी से कम नहीं लगती। वर्तमान वैश्विक राजनीति में सबसे चिंताजनक बात यह है कि नेताओं की भाषा से संवेदनशीलता कम होती जा रही है। राजनीतिक मंचों पर संवाद के स्थान पर कटुता और धमकियों का प्रयोग बढ़ गया है। सोशल मीडिया और प्रचार तंत्र ने भी आक्रामक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है। जनता को भावनात्मक रूप से उकसाकर युद्ध समर्थक वातावरण तैयार किया जाता है। राष्ट्रहित के नाम पर हिंसा को उचित ठहराया जाने लगा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा था कि विश्व शांति सहअस्तित्व और पारस्परिक सम्मान से ही संभव है। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से यह संदेश दिया कि शक्ति संतुलन युद्ध से नहीं बल्कि संवाद से कायम रखा जा सकता है। किंतु आज विश्व राजनीति में संवाद की जगह आर्थिक प्रतिबंध,सैन्य गठबंधन और हथियारों का प्रदर्शन अधिक दिखाई देता है।

दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था—यदि आप अपने शत्रु के साथ शांति चाहते हैं तो आपको उसके साथ काम करना होगा। यह कथन बताता है कि शांति केवल समझौतों से नहीं बल्कि मानसिक परिवर्तन से आती है। दुर्भाग्यवश वर्तमान विश्व नेतृत्व में यह मानसिक परिपक्वता कम दिखाई देती है। नेताओं के निर्णय अक्सर अहंकार,राजनीतिक लाभ और चुनावी रणनीतियों से प्रभावित होते हैं। मानवता पीछे छूट जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों को भी कई बार राजनीतिक नेतृत्व अपने हित में उपयोग करता है। इससे समाजों में अविश्वास और घृणा बढ़ती है। दुनिया का सामान्य नागरिक शांति चाहता है,लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे लोग संघर्ष से लाभ अर्जित करते हैं। हथियार कंपनियों का बढ़ता प्रभाव भी विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। युद्ध जितना लंबा चलता है,हथियार उद्योग उतना अधिक लाभ कमाता है। ऐसे में शांति प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं। भारत की सांस्कृतिक परंपरा सदैव 'वसुधैव कुटुंबकम्' की रही है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व बंधुत्व की बात की। फिर भी आधुनिक विश्व ने इन आदर्शों को केवल भाषणों तक सीमित कर दिया है। यदि विश्व नेतृत्व वास्तव में शांति चाहता,तो शिक्षा,स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उतना ही खर्च होता जितना हथियारों पर किया जा रहा है। आज आवश्यकता केवल राजनीतिक समझौतों की नहीं,बल्कि मानसिक क्रांति की है। विश्व नेताओं को यह समझना होगा कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। युद्ध केवल विनाश की नई नींव रखता है। शांति कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो नेता संवाद,सहिष्णुता और मानवता की रक्षा करते हैं,इतिहास अंततःउन्हीं को महान मानता है। अंततःयह कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से भ्रमित वैश्विक नेतृत्व ने दुनिया को भय,असुरक्षा और संघर्ष के द्वार पर ला खड़ा किया है। यदि समय रहते शांति, सहअस्तित्व और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता नहीं दी गई।

राजेन्द्र लाहिरी
पामगढ़ छग

कुर्सी की गंध

यह गंध बड़ी ही न्यारी है,
नेताओं को लगती प्यारी है,
चमचों की टोली डोल रही,
हर गली सुगंधी घोल रही,
यह गंध नहीं है फूलों की,
यह बू है भूखे व्याकुलों की,
जो पहले चरणों में गिरते,
हाथों में झोली ले फिरते,
बनकर के दीन और लाचार,
मांगते फिरते हैं अधिकार,
फिर जन-मस्तिष्क पर चढ़ जाते,
अपनी ही ढपली बजाते,
पैसों की बोरी खुलती है,
ईमान की हस्ती धुलती है,
बोतल से मौसम बनता है,
हर वोटर भीतर तनता है,
यह खेल बड़ा ही भारी है,
बस पांच बरस की यारी है,
फिर जैसे ही चुनाव बीता,
सब भूल गए कौन हारा-जीता,
खातों की बही निकालते हैं,
पाई का हिसाब संभालते हैं,
चमचों को मिलता माल नया,
जनता पूछे भैया,क्या आया?
सिंहासन मिलते ही बदले,
जो कल तक थे बिल्कुल पतले,
अब ठाठ-बाठ हैं भारी जी,
बन बैठे खड्ग त्रिधारी जी,
स्वयंभू भगवान कहाते हैं,
हमको ही आंख दिखाते हैं,
यह गंध व्यवस्था की सड़न,
जनता के मन की है जलन।

चेंजिंग रूम में हिडन कैमरे

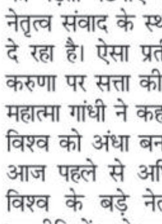

डॉ.प्रियंका सौरभ

हर सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने नागरिकों की गरिमा,निजता और सुरक्षा को कितना महत्व देता है। विशेषकर महिलाओं की निजता की रक्षा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल दायित्व है। लेकिन जब ऐसे स्थान,जहाँ व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित समझता है–जैसे चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम,फोटो स्टूडियो,जिम, ब्यूटी पार्लर या होटल–वहीं उसकी निजता पर हमला होने लगे,तब यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी बन जाती है। हिसार के निरंकारी रोड स्थित एक फोटो स्टूडियो के चेंजिंग रूम में कथित रूप से हिडन कैमरा मिलने की घटना ने हर संवेदनशील नागरिक को झकझोर दिया है। जानकारी के अनुसार,फोटो शूट के लिए पहुँची एक युवती ने चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते समय दीवार में कुछ संदिग्ध दिखाई देने पर अपने मोबाइल की टॉर्च से जांच की और एक छिपा हुआ कैमरा देखा। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी,जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैमरा जब्त किया और स्टूडियो संचालक को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस घटना को केवल एक पुलिस केस मानकर भुलाया न जाए,बल्कि इसे समाज, प्रशासन और कानून के लिए गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जाए। यह घटना अनेक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या यह कैमरा पहली बार लगाया गया था? क्या इससे पहले भी किसी की रिकॉर्डिंग की गई? यदि रिकॉर्डिंग हुई, तो वह कहाँ संग्रहीत है? क्या उसे किसी के साथ साझा किया गया? क्या अन्य लोग भी इस अपराध का शिकार हुए होंगे? इन सभी पहलुओं की वैज्ञानिक और डिजिटल फॉरेंसिक जांच अत्यंत आवश्यक है। ऐसे मामलों में केवल कैमरा बरामद करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े प्रत्येक डिजिटल साक्ष्य की जांच भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन उसी तकनीक का दुरुपयोग अपराधियों के हाथों में खतरनाक हथियार बन गया है।

आज बाजार में अत्यंत छोटे आकार के कैमरे आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें घड़ी, पेन, चार्जर, स्मोक डिटेक्टर,बल्ब,हुक,पावर बैंक या सजावटी वस्तुओं में छिपाया जा सकता है। आम व्यक्ति के लिए उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। यही कारण है कि ऐसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और कई बार पीड़ितों को वर्षों तक पता भी नहीं चलता कि उनकी निजी गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। ऐसे अपराध केवल निजता का उल्लंघन नहीं करते,बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि किसी महिला को यह पता चले कि उसके कपड़े बदलते समय की वीडियो रिकॉर्डिंग किसी ने बना ली है,तो वह केवल कानूनी पीड़िता नहीं रहती,बल्कि लंबे समय तक मानसिक तनाव,भय,शर्म और सामाजिक दबाव से भी गुजरती है। कई मामलों में पीड़ित अवसाद, आत्मग्लानि और सामाजिक अलगाव का भी सामना करते हैं। इसलिए ऐसे अपराधों को केवल तकनीकी अपराध नहीं,बल्कि मानवीय गरिमा पर हमला माना जाना चाहिए। इस घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष विश्वास का टूटना है। कोई भी व्यक्ति फोटो स्टूडियो में इस विश्वास के साथ जाता है कि वहाँ उसकी निजता सुरक्षित रहेगी।

सुविचार

प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और **प्रयास** ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है...

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
–सम्पादक

15 साल से गड्ढों में दफन विकास : डिगमा-सरगवां सड़क पर फूटा जनाक्रोश,24 जुलाई को चक्का जाम की चेतावनी

बनारस रोड को प्रतापपुर रोड से जोड़ने वाला अहम मार्ग बदहाल...स्कूल,कॉलेज और एफसीआई के भारी वाहनों का दबाव, फिर भी निर्माण नहीं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। विकास के दावों के बीच शहर से सटे डिगमा-सरगवां मार्ग की तस्वीर सरकारी व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। बनारस रोड को प्रतापपुर रोड से जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क पिछले करीब 15 वर्षों से बदहाली का शिकार है। जगह-जगह बड़े गड्ढे,उखड़ी डामर परत और धूल के गुबार अब इस सड़क की पहचान बन चुके हैं।

हालत यह है कि रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही वाले इस मार्ग पर चलना भी जोखिम भरा हो गया है। लगातार उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों, महिला समूहों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने अब आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। यदि प्रशासन ने तत्काल निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया तो 24 जुलाई को सुबह 11 बजे बनारस रोड स्थित साईं बाबा कॉलेज के पास चक्का जाम और सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इसकी सूचना एसडीएम अंबिकापुर को भी सौंप दी गई है।

करोड़ों के विकास दावों के बीच सड़क बदहाल

यह सड़क केवल एक गांव का संपर्क मार्ग नहीं, बल्कि साईं बाबा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, साईं बाबा स्कूल और एफसीआई के चावल गोदाम तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है। प्रतिदिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं, शिक्षक, कर्मचारी और ग्रामीण इसी मार्ग से गुजरते हैं। वहीं एफसीआई गोदाम तक पहुंचने वाले भारी ट्रकों की लगातार आवाजाही ने सड़क को पूरी तरह तोड़ दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षमता से अधिक भार वाले वाहनों का संचालन वर्षों से हो रहा है, लेकिन सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण को लेकर जिम्मेदार विभागों ने गंभीरता नहीं दिखाई।

सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और बच्चों को

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की बदहाली का सबसे अधिक असर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और स्कूल जाने वाले बच्चों पर पड़ रहा है। बारिश के दिनों में गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं, जबकि एंबुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं का संचालन भी प्रभावित होता है।

बार-बार शिकायत,फिर भी कार्रवाई नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सड़क की स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। वर्षों बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं होने से लोगों में गहरा आक्रोश है। अब आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 24 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन के दौरान बनारस रोड (एनएच-43) और डिगमा-सरगवां मार्ग का आवागमन प्रभावित हो सकता है। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर के माध्यम से शासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।उल्लेखनीय है कि यह केवल सड़क निर्माण का मुद्दा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवागमन से जुड़ा जनहित का प्रश्न है। जिस मार्ग से प्रतिदिन विद्यार्थी,मरीज,महिलाएं और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन होता हो, उसकी वर्षों तक उपेक्षा प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि समय रहते सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो यह समस्या किसी बड़े हादसे का कारण भी बन सकती है।

रेलवे स्टेशन से लापता नाबालिग मिला,ग्रामीणों की सतर्कता से सुरक्षित पहुंचा पुलिस तक

गांझाडांड में लावारिस हालत में मिला था बच्चा,रघुनाथपुर चौकी से आरपीएफ को सौंपा गया,दूसरे मामले में घर में छिपा मिला नाबालिग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। रेलवे स्टेशन अंबिकापुर से लापता हुए एक नाबालिग बालक को सरगुजा पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर आरपीएफ के सुपुर्द कर दिया। बालक गांझाडांड गांव में लावारिस हालत में मिला था, जहां ग्रामीणों की सतर्कता और मानवीय पहल से उसे सुरक्षित रखकर पुलिस तक पहुंचाया गया। वहीं एक अन्य मामले में घर से लापता बताए गए नाबालिग को पुलिस ने कुछ ही समय में उसके घर से बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार 15 जुलाई को एक व्यक्ति ने थाना गांधीनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि रेलवे स्टेशन अंबिकापुर से उसके नाबालिग पुत्र को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। शिकायत पर शून्य (जीरो) एफआईआर दर्ज कर मामले की जानकारी संबंधित एजेंसी को भेजी गई और नाबालिग की तलाश शुरू की गई।

ग्रामीणों ने निभाई जिम्मेदारी : इसी दौरान गांझाडांड गांव के कुछ ग्रामीणों को एक नाबालिग बालक लावारिस हालत में मिला। उन्होंने पहले आसपास परिजनों की तलाश की,लेकिन जानकारी नहीं मिलने पर बच्चे को सुरक्षित अपने पास रखा और बाद में रघुनाथपुर चौकी पहुंचाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पहचान कराने पर पुष्टि हुई कि यही रेलवे स्टेशन अंबिकापुर से लापता हुआ नाबालिग है। इसके

बाद पुलिस ने बच्चे को आरपीएफ अंबिकापुर के हवाले कर दिया।

पढ़ाई से बचने के लिए घर में छिप गया था दूसरा बालक : एक अन्य मामले में एमजी रोड निवासी व्यक्ति ने अपने नाबालिग पुत्र के घर से गायब होने की सूचना थाना गांधीनगर में दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल तलाश शुरू की और बालक को उसके ही घर से बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि वह पढ़ाई से बचने के लिए घर में ही छिपा हुआ था। बाद में उसे परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने कहा कि गुमशुदा नाबालिगों के मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जा रही है और आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी लावारिस या संदिग्ध परिस्थिति में मिले बच्चे की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

क्रिप्टो में 10 गुना मुनाफे का झांसा...10 हजार की ठगी,सरगुजा पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा

होटल में सेमिनार कर Bitget Wallet (LGNS) में निवेश के नाम पर लोगों को फंसाते थे, लैपटॉप-प्रोजेक्टर सहित कई सामान जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। क्रिप्टोकरेंसी में एक साल में 10 हजार रुपये को एक लाख रुपये बनाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का सरगुजा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मणीपुर थाना पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्पीकर, मोबाइल, डायरी समेत अन्य सामग्री जब्त की है। मामले में कुछ अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार इंदरपुर निवासी विद्याचरण राव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव के त्रिपाल टोप्पो ने ऑनलाइन निवेश से अधिक मुनाफा होने का लालच देकर उसकी मुलाकात उदयपुर निवासी राजकुमार पैकरा से कराई। इसके बाद 19 जुलाई को अंबिकापुर के होटल फिल आनंदम में आयोजित एक सेमिनार में उसे Bitget Wallet (LGNS) के जरिए निवेश करने पर एक वर्ष में 10 हजार रुपये के बदले एक लाख रुपये मिलने का दावा किया गया। झांसे में आकर उसने 10 हजार रुपये नकद दे दिए, जिसके बाद खुद को ठगा महसूस होने पर पुलिस में शिकायत की।

होटल में चल रहा था निवेश का सेमिनार

जांच में सामने आया कि होटल फिल आनंदम में लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से 10 से 12 लोगों को क्रिप्टो निवेश की ट्रेनिंग दी जा रही थी। निवेशकों को बताया जा रहा था कि अलग-अलग लेवल पूरे करने पर बिना मेहनत के लगातार मुनाफा मिलता रहेगा। पुलिस ने मौके और जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तार आरोपियों में कान्ता प्रसाद राजवाड़े,राजकुमार पैकरा,जीवन साय टोप्पो,फिरोज लकड़ा और मुकेश कुमार गुप्ता शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें बिलासपुर के त्रिभुवन साहू और रमाशंकर साहू ने इस तरह के निवेश मॉडल की जानकारी दी थी तथा वे विभिन्न स्थानों पर सेमिनार आयोजित कर लोगों को जोड़ रहे थे।

लैपटॉप,प्रोजेक्टर और मोबाइल जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, लैपटॉप बैग,चार्जर,प्रोजेक्टर,स्पीकर,मोबाइल फोन, तीन डायरी, एक नोटबुक और एक टी-शर्ट जब्त की है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जांच के दौरान दूसरे राज्यों एवं जिलों तक नेटवर्क के फैलाव की जानकारी भी मिली है।

लालच में न आएं: पुलिस

सरगुजा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अधिक मुनाफे के लालच में किसी भी अनजान या भ्रामक ऐप अथवा निवेश योजना में पैसा न लगाएं। निवेश से पहले संबंधित प्लेटफॉर्म की वैधता की जांच अवश्य करें, अन्यथा साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं।

पुलिस की कार्रवाई:डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना मणीपुर प्रभारी उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी और उनकी टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया।

पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन,घड़ी चौक पर फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग,परीक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। परीक्षा प्रश्नपत्र लीक के मामलों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने संयुक्त रूप से अंबिकापुर के घड़ी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। नेताओं ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में

पारदर्शिता सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जिला कांग्रेस के महामंत्री एवं युवा कांग्रेस-एनएसयूआई प्रभारी आलोक सिंह ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात सुनने के बजाय उनके साथ बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली आवश्यक है। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, शफी अहमद, राकेश गुप्ता, हेमंत सिन्हा, इंदरजीत सिंह धंजल, संजीव मंदिलवार, मैदान जायसवाल, असफाक अली, संजय सिंह, जीवन यादव, आलोक सिंह, अमित कुमार सिंह (रिंकू), सोहन जायसवाल, अविनाश कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और छात्र संगठन के सदस्य उपस्थित रहे।

होली क्रॉस के 81 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर बनाया नया रिकॉर्ड

दूसरी बोर्ड परीक्षा के बाद तीन और छात्र जुड़े मेरिट सूची में,दो विद्यार्थियों ने 98.4% अंक प्राप्त किया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा सत्र 2025-26 से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए लागू दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली का लाभ होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) के विद्यार्थियों को मिला है। दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद विद्यालय के 81 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार पहली बोर्ड परीक्षा के परिणाम में 78 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे। बेहतर प्रदर्शन के उद्देश्य से 46 विद्यार्थियों ने दूसरी बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया। परिणाम घोषित होने पर समर जायसवाल (91.2%), सृष्टि सिन्हा (91%) और नरगिस खातून (90.6%) ने भी 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय की गौरव सूची में अपना स्थान बनाया। इसके साथ ही 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 81 हो गई। विद्यालय की एक और उपलब्धि यह रही कि पहली

परीक्षा में पुष्कल सिंह ने 98.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान हासिल किया था। दूसरी परीक्षा के बाद अभिषेक सोनी ने भी 98.4 प्रतिशत अंक अर्जित कर संयुक्त रूप से विद्यालय के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में अपना नाम दर्ज कराया। विद्यालय की प्राचार्या डॉ. सिस्टर जेस्सी थेक्कन ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग से विद्यालय लगातार उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद भी अटकी अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन...एक माह से तारीख का इंतजार

द्वि-साप्ताहिक संचालन को 19 जून को मिली थी स्वीकृति,अब तक शेड्यूल घोषित नहीं; यात्रियों में बढ़ी नाराजगी...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अंबिकापुर से दिल्ली के बीच चलने वाली बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस ट्रेन को द्वि-साप्ताहिक किए जाने की रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के एक माह बाद भी संचालन की तारीख घोषित नहीं होने से सरगुजा संभाग के यात्रियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उत्तर छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को अब भी अतिरिक्त फेरे शुरू होने का इंतजार है। रेलवे बोर्ड ने 19 जून 2026 को ट्रेन संख्या 22407/22408 अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस को साप्ताहिक से बढ़ाकर द्वि-साप्ताहिक संचालित करने की स्वीकृति दी थी। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार ट्रेन संख्या 22407 अंबिकापुर से प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार, जबकि 22408 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक रविवार और मंगलवार को चलनी है। हालांकि स्वीकृति के बाद भी अब तक संचालन की तिथि तय नहीं की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य मुकेश तिवारी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि बोर्ड की मंजूरी के बावजूद संचालन में हो रही देरी यात्रियों की उम्मीदों के विपरीत है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर जल्द से जल्द नई तिथि घोषित की जानी चाहिए।

विद्यार्थियों, मरीजों और व्यापारियों को सबसे ज्यादा परेशानी

दूसरा फेरा शुरू नहीं होने से सरगुजा संभाग,उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को हर सप्ताह सीटों की कमी और लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे अधिक असर दिल्ली आने-जाने वाले विद्यार्थियों,इलाज के लिए यात्रा करने वाले मरीजों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों पर पड़ रहा है।

यात्रियों की मांग...अब और इंतजार नहीं...

क्षेत्रीय नागरिकों और रेल यात्रियों ने रेल मंत्रालय से मांग की है कि रेलवे बोर्ड की स्वीकृति को जल्द अमल में लाते हुए द्वि-साप्ताहिक सेवा की संचालन तिथि तत्काल घोषित की जाए,ताकि लंबे समय से लंबित इस सुविधा का लाभ लोगों को मिल सके।

राज्य स्तरीय ऑर्गन डोनेशन समिति में सरगुजा की मजबूत भागीदारी,चार को मिली जिम्मेदारी

रेड क्रॉस के 'रक्तदान महादान-अंगदान जीवनदान' अभियान को मिली पहचान,आकांक्षा श्रीवास्तव बनीं वाइस चेयरमैन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा सरगुजा के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा द्वारा गठित 15 सदस्यीय राज्य स्तरीय ऑर्गन डोनेशन समिति में सरगुजा जिले के चार प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें आकांक्षा श्रीवास्तव को समिति का वाइस चेयरमैन बनाया गया है, जबकि अंजुला गौतम मिश्रा, संध्या सिंह और आर्यन सिन्हा को राज्य स्तरीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। विशेष बात यह है कि समिति में सरगुजा से तीन महिला प्रतिनिधियों को स्थान मिला है, जिसे जिले के लिए सम्मानजनक उपलब्धि माना जा रहा है। रेड क्रॉस जिला शाखा के अनुसार यह सफलता वर्षों से चलाए जा रहे 'रक्तदान महादान-अंगदान जीवनदान' जनजागरूकता अभियान और स्वयंसेवकों के सतत प्रयासों का परिणाम है।

राज्यपाल को सौंपा गया मांग-पत्र : रायपुर में आयोजित समिति की पहली बैठक में सरगुजा के प्रतिनिधियों ने नेत्रदान, अंगदान और देहदान को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। बैठक के बाद राज्य शाखा के चेयरमैन तोमन साहू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में शिष्टाचार भेंट कर मांग-पत्र सौंपा। मांग-पत्र में अंगदान एवं देहदान करने वाले व्यक्तियों को मरणोपरांत गार्ड ऑफ ऑनर देने, विश्व अंगदान दिवस (13 अगस्त) पर अंगदाता परिवारों, चिकित्सकों और ट्रांसप्लांट समन्वयकों का राज्य स्तरीय सम्मान करने सहित कई सुझाव शामिल किए गए।

राज्यपाल ने की पहल की सराहना : राज्यपाल ने समिति की मानवीय पहल की सराहना करते हुए प्रस्तावों पर सकारात्मक मार्गदर्शन दिया और आवश्यक शासन स्तर की कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर समाज में अंगदान, नेत्रदान और देहदान के प्रति व्यापक जनजागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। रेड क्रॉस जिला शाखा के चेयरमैन अदितेश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि यह सम्मान केवल चार प्रतिनिधियों का नहीं, बल्कि सरगुजा के पूरे रेड क्रॉस परिवार, स्वयंसेवकों,रक्तदाताओं और समाजसेवियों के वर्षों के समर्पण का सम्मान है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य स्तरीय समिति छत्तीसगढ़ में अंगदान और मानव सेवा के अभियान को नई दिशा देगी।

आईसी मार्ट प्रकरण में नया मोड़

व्यापारियों ने एसपी से कहा- 'आरोपी पकड़िए, परिवार को नहीं'

संचालक के भाई ने पथराव और भीड़ के खिलाफ एफआईआर की मांग की

- व्यापारी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा एसपी कार्यालय
- परिवार की महिलाओं को थाने में बैठाने पर जताई नाराजगी
- परिवार बोला- रोज-रोज की प्रताड़ना से अच्छा जेल भेज दीजिए
- 19 जुलाई के प्रदर्शन को बताया पूर्व नियोजित
- पथराव, गाली-गलौज और भय का आरोप
- सीसीटीवी, वीडियो सुरक्षित रखने और एफआईआर की मांग

आत्महत्या की जांच या परिवार की प्रताड़ना?

बैकुंठपुर प्रकरण में पुलिस कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

बैकुंठपुर आत्महत्या मामला,आरोपी नहीं मिले तो परिवार पर शिकंजा? व्यापारियों ने एसपी से उठाई आवाज

फरार आरोपी अब भी बाहर,लेकिन परिवार थाने में! बैकुंठपुर आत्महत्या मामले में पुलिस कार्रवाई पर बहस तेज

'आरोपी पकड़िए, परिवार नहीं'– बैकुंठपुर में व्यापारियों का पुलिस से सवाल, आईसी मार्ट परिवार ने सुनाई अपनी पीड़ा

आत्महत्या से आगे बढ़ा बैकुंठपुर कांड पुलिस कार्रवाई,व्यापारी विरोध और प्रताड़ना के आरोपों के बीच उलझी जांच

संचालक के भाई ने पथराव और भीड़ के खिलाफ एफआईआर की मांग की

एसपी कार्यालय पहुंचे व्यापारी,परिवार की महिलाओं को थाने में बैठाने पर जताई आईसी मार्ट प्रकरण में नया मोड़,व्यापारियों का पुलिस पर सवाल, संचालक के भाई ने भीड़,पथराव और भय फैलाने वालों पर एफआईआर की मांग की...

-रवि सिंह-

कोरिया/बैकुंठपुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। आईसी मार्ट आत्महत्या प्रकरण अब लगातार नए मोड़ ले रहा है, एक ओर जहां फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस की कार्रवाई को लेकर व्यापारी वर्ग खुलकर सामने आ गया है,वहीं दूसरी ओर आईसी मार्ट संचालक के भाई ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर प्रदर्शन के दौरान हुई कथित हिंसा,पथराव और भय का वातावरण बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, इन घटनाक्रमों ने पूरे मामले को केवल आत्महत्या की विवेचना तक सीमित नहीं रहने दिया है, बल्कि अब पुलिस कार्रवाई,कानून-व्यवस्था और विरोध प्रदर्शन की वैधता भी चर्चा का विषय बन गई है।

बैकुंठपुर के चर्चित आईसी मार्ट आत्महत्या प्रकरण में अब घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है,जहां एक ओर पुलिस आत्महत्या के मामले में दर्ज अपराध के फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है,वहीं दूसरी ओर व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाता नजर आया,व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि कानून के दायरे में रहकर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए,लेकिन आरोपियों के परिवार की महिलाओं,बच्चों और निर्दोष परिजनों को थाने में बैठाकर मानसिक प्रताड़ना न दी जाए,इसी बीच आईसी मार्ट संचालक के भाई महेंद्र कुमार बैद ने पुलिस अधीक्षक को दो पृष्ठों का विस्तृत आवेदन देकर पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है, आवेदन में उन्होंने 19 जुलाई को आईसी मार्ट के सामने हुए प्रदर्शन को पूर्व नियोजित बताते हुए भीड़ जुटाने, पथराव, गाली-गलौज,भय का वातावरण बनाने और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित रखकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

व्यापारियों ने एसपी से की सीधी बातचीत- सोमवार को बैकुंठपुर के कई व्यापारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे,प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मुलाकात कर कहा कि उन्हें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी से कोई आपत्ति नहीं है,बल्कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए,लेकिन कार्रवाई करते समय पूरे परिवार को प्रताड़ित करना उचित नहीं है,व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से परिवार की महिलाओं और बच्चों को भी थाने बुलाकर घंटों बैठाया जा रहा है,इससे पूरे व्यापारी समाज में असंतोष का माहौल है,सूत्रों के अनुसार व्यापारियों की मुलाकात के बाद थाने में बैठे परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया,हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

प्रतिष्ठान बंद है,परिवार भय में जी रहा है...

परिजनों का कहना है कि घटना के बाद से उनका प्रतिष्ठान बंद है और व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो चुका है,उनका दावा है कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के कारण परिवार के सदस्य सामान्य जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं,परिवार का कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कभी भी पुलिस जांच से इंकार नहीं किया, उनका कहना है कि यदि किसी सदस्य के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन पूरे परिवार को संदेह के आधार पर प्रताड़ित करना उचित नहीं है।

हम न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं,भीड़ पर नहीं...

परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है,उनका कहना है कि किसी भी व्यक्ति का दोष या निर्दोष होना न्यायालय तय करता है,न कि सड़क पर जुटी भीड़,परिजनों का कहना है कि यदि कानून उन्हें दोषी मानता है तो वे न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे,लेकिन किसी सामाजिक या जन दबाव के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

परिवार बोला- रोज-रोज की प्रताड़ना से तंग आ चुके हैं-

आईसी मार्ट परिवार का कहना है कि आत्महत्या मामले के बाद से लगातार उनके घर के लोगों को पूछताछ के नाम पर बुलाया जा रहा है, परिवार का आरोप है कि यदि पुलिस के पास किसी के विरुद्ध साक्ष्य हैं तो उसे गिरफ्तार करे, लेकिन महिलाओं और बच्चों को लगातार थाने में बैठाना मानसिक प्रताड़ना है, परिवार के सदस्यों का कहना है कि यदि पूरे परिवार को आरोपी मानना है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन रोज-रोज बुलाकर अपमानित न किया जाए, इन आरोपों पर पुलिस की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

महेंद्र बैद का आवेदन बना नया केंद्र-

घटनाक्रम के बीच आईसी मार्ट संचालक के भाई महेंद्र कुमार बैद द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया गया आवेदन अब चर्चा का विषय बन गया है, आवेदन में कहा गया है कि 19 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग 3:40 बजे आईसी मार्ट के सामने लगभग 200 या उससे अधिक लोगों की भीड़ एकत्र हुई, आवेदन के अनुसार भीड़ ने नारेबाजी, गाली-गलौज, हिंसक प्रदर्शन किया और प्रतिष्ठान पर पथराव किया। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि पेट्रोल बम से हमला करने का प्रयास किया गया, जिससे प्रतिष्ठान, कर्मचारियों और परिवार की जान-माल को खतरा उत्पन्न हुआ।

रोज-रोज की प्रताड़ना से अच्छा एक बार कार्रवाई कर दें...

परिवार के एक सदस्य ने भावुक होकर कहा कि यदि पुलिस को लगता है कि पूरा परिवार दोषी है तो सभी को एक साथ जेल भेज दिया जाए,लेकिन रोज-रोज महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को थाने बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए,उनका कहना है कि लगातार पूछताछ और दबाव के कारण परिवार के सभी सदस्य मानसिक रूप से टूट चुके हैं।

पुलिस की विवेचना पर भी उठाए सवाल-

परिवार का दावा है कि घटना को लगभग दस दिन बीत चुके हैं,लेकिन अभी तक आत्महत्या के वास्तविक कारणों को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है,उनका आरोप है कि विवेचना का पूरा ध्यान फरार आरोपियों के बजाय परिवार पर दबाव बनाने पर केंद्रित दिखाई दे रहा है, हालांकि पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी सार्वजनिक नहीं की गई है।

यह स्वतः नहीं,पूर्व नियोजित प्रदर्शन था...

महेंद्र बैद ने अपने आवेदन में दावा किया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ पहुंचना इस बात की ओर संकेत करता है कि प्रदर्शन पूर्व नियोजित और संगठित था,उन्होंने पुलिस से मांग की है कि यह जांच की जाए कि भीड़ किसने जुटाई,किसके कहने पर लोग आए और प्रदर्शन को उग्र बनाने में किन लोगों की भूमिका थी।

नाबालिगों को शामिल करने का भी आरोप

आवेदन में कहा गया है कि प्रदर्शन में कुछ नाबालिग बच्चों को भी शामिल किया गया था, यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है तो इसकी भी अलग से जांच की जानी चाहिए।

सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो सुरक्षित रखने की मांग...

महेंद्र बैद ने पुलिस से आग्रह किया है कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो, फोटोग्राफ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित किया जाए ताकि किसी भी साक्ष्य के नष्ट होने की संभावना न रहे, उनका कहना है कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक दोषियों की पहचान की जा सकती है।

एफआईआर दर्ज करने की मांग...

आवेदन में महेंद्र बैद ने आग्रह किया है कि उनके आवेदन को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों तथा अन्य लागू धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाए और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

पुलिस का पक्ष आना बाकी

समाचार लिखे जाने तक पुलिस की ओर से परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, मामले की विवेचना जारी है और फरार आरोपियों की तलाश भी पुलिस द्वारा की जा रही है।

पुलिस समय पर हस्तक्षेप करती तो शायद जान बच सकती थी...

परिवार का यह भी दावा है कि घटना से पहले पुलिस को जानकारी मिली थी और संबंधित प्रतिष्ठान में पुलिस की मौजूदगी भी हुई थी, उनका कहना है कि यदि उस समय प्रभावी हस्तक्षेप किया जाता तो संभव है कि आगे की दुखद घटना टल सकती थी, यह परिवार का दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

क्या विरोध प्रदर्शन कानून की सीमा में रहा?

महेंद्र बैद के आवेदन ने अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, यदि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में पथराव,हिंसा या भय का वातावरण बनाने जैसी घटनाएं हुई हैं, तो उनकी अलग से जांच होगी या नहीं? दूसरी ओर प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि उनका उद्देश्य मृत छात्रा को न्याय दिलाने की मांग करना था,ऐसे में अब पुलिस को दोनों पक्षों के दावों की जांच करनी होगी।

पुलिस के सामने दोहरी जिम्मेदारी

अब पुलिस के सामने दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं पहली,आत्महत्या प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना पूरी करना और फरार आरोपियों को गिरफ्तार करना, दूसरी,19 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान यदि कानून-व्यवस्था भंग हुई, पथराव या अन्य आपराधिक घटनाएं हुईं,तो उनकी भी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

शहर में बढ़ी चर्चा,सभी की नजर पुलिस पर

आईसी मार्ट प्रकरण अब केवल आत्महत्या के मामले तक सीमित नहीं रह गया है, इसमें पुलिस की विवेचना,व्यापारियों की नाराजगी,परिवार पर कथित दबाव,सार्वजनिक प्रदर्शन और अब प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा से जुड़े आरोप भी शामिल हो गए हैं,व्यापारी समाज चाहता है कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए,वहीं मृत छात्रा के पक्ष में प्रदर्शन करने वाले लोग दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस विवेचना और महेंद्र बैद के आवेदन पर आगे क्या कदम उठाती है।

संलग्नीकरण खत्म... या सिर्फ नाम बदला?

संलग्नीकरण समाप्ति के बाद नया आदेश...27 शिक्षक फिर पहुंचे छात्रावास,अब कोरिया की बारी?

शासन ने खत्म किया संलग्नीकरण,एमसीबी ने निकाला नया फॉर्मूला! 27 शिक्षकों को मिला दोहरा दायित्व

संलग्नीकरण खत्म... या सिर्फ नाम बदला? एमसीबी में 27 शिक्षकों को फिर मिला छात्रावासों का जिम्मा

स्कूल भी,छात्रावास भी : संलग्नीकरण खत्म होने के बाद एमसीबी का नया प्रयोग चर्चा में...

संलग्नीकरण पर नया 'फॉर्मूला',एमसीबी में 27 शिक्षकों को अतिरिक्त प्रभार,उठे कई सवाल

शिक्षा विभाग का आदेश और एमसीबी का मॉडल,खत्म हुआ संलग्नीकरण या बदल गई परिभाषा?

स्कूल लौटे शिक्षक,फिर मिला छात्रावास का जिम्मा, एमसीबी के आदेश पर प्रशासनिक बहस तेज

एक आदेश खत्म, दूसरा शुरू! एमसीबी में 'अतिरिक्त प्रभार' ने फिर छेड़ी संलग्नीकरण की बहस

संलग्नीकरण खत्म...या सिर्फ नाम बदला? एमसीबी में 27 शिक्षकों को फिर मिला छात्रावासों का जिम्मा,नए आदेश ने खड़े किए कई सवाल

-रवि सिंह-

एमसीबी/कोरिया,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। शिक्षा विभाग में वर्षों से विवाद का विषय रही संलग्नीकरण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राज्य शासन ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया था,सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि शिक्षा विभाग के शिक्षक और गैर शिक्षकीय कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटेंगे और सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त किए जाएंगे, शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि शिक्षक पढ़ाने के लिए हैं,इसलिए उन्हें स्कूलों में ही रहना चाहिए। इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश में हलचल मच गई, वर्षों से विभिन्न कार्यालयों,आश्रम-छात्रावासों और अन्य संस्थाओं में कार्यरत संलग्न शिक्षकों के बीच बेचैनी बढ़ गई,कई जिलों में कलेक्टरों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश जारी किए,एमसीबी और कोरिया जिले में भी आदिम जाति विकास विभाग के छात्रावासों में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में लौटने के आदेश जारी हो गए,ऐसा लगा कि अब संलग्नीकरण का अध्याय समाप्त हो जाएगा,लेकिन कुछ ही दिनों बाद एमसीबी जिले से जारी एक नए आदेश ने पूरे मामले को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया।

27 शिक्षकों को फिर मिला छात्रावास का दायित्व

15 जुलाई 2026 को कलेक्टर (आदिवासी विकास) कार्यालय,एमसीबी द्वारा जारी आदेश में जिले के 27 शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हुए विभिन्न आश्रम एवं छात्रावासों का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया,आदेश में स्पष्ट किया गया कि संबंधित कर्मचारी अपने मूल पद पर कार्य करेंगे,साथ ही छात्रावासों की व्यवस्थाओं का संचालन भी करेंगे, उनका वेतन मूल संस्था से ही आहरित होगा तथा नियमानुसार अन्य प्रावधान लागू रहेंगे,यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया।

संलग्नीकरण खत्म हुआ या उसकी परिभाषा बदल गई?

शासन के आदेश का मूल उद्देश्य था कि शिक्षक केवल अपने विद्यालयों में रहें और अध्यापन कार्य प्रभावित न हो,लेकिन अब जब वही शिक्षक स्कूल के साथ-साथ छात्रावास भी संभालेंगे,तो शिक्षा जगत में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वास्तव में व्यवस्था बदली है,या केवल उसका नाम बदल गया है? पहले शिक्षक छात्रावास में 'संलग्न' थे,अब वे 'अतिरिक्त दायित्व' निभाएंगे,फाइलों की भाषा बदल गई, लेकिन जमीन पर व्यवस्था कितनी बदली,यही सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है।

स्कूल भी...छात्रावास भी...आखिर कैसे?- सरकारी आदेशों में दोहरी जिम्मेदारी लिख देना आसान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था कितनी सफल होगी? एक शिक्षक को प्रतिदिन विद्यालय में अध्यापन करना है। वहीं छात्रावास अधीक्षक के रूप में उसे विद्यार्थियों की उपस्थिति, भोजन, स्वास्थ्य, अनुशासन, सुरक्षा, अभिभावकों से संपर्क,आकस्मिक परिस्थितियों और रात्रिकालीन व्यवस्था पर भी नजर रखनी होगी,ऐसे में प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या दोनों जिम्मेदारियां समान गुणवत्ता के साथ निभाई जा सकेंगी? यदि शिक्षक विद्यालय में रहेंगे तो छात्रावास कौन देखेगा, और यदि छात्रावास में अधिक समय देंगे तो विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित होगी या नहीं?

सरकार का उद्देश्य क्या था?

शासन द्वारा संलग्नीकरण समाप्त करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि अनेक शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में न जाकर अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे हैं,जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी पैदा हो रही है,सरकार का उद्देश्य था कि प्रत्येक शिक्षक अपने मूल विद्यालय में लौटे और विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई मिल सके,अब यदि अतिरिक्त दायित्व के नाम पर वही शिक्षक फिर छात्रावासों में जिम्मेदारी निभाने लगें,तो इस निर्णय के मूल उद्देश्य को लेकर भी चर्चा होना स्वाभाविक है।

निकटस्थ संकुल का नया फॉर्मूला

जारी आदेश का अवलोकन करने पर यह भी सामने आता है कि अधिकांश मामलों में संबंधित छात्रावासों के निकट स्थित विद्यालयों के शिक्षकों को ही अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासन ने दूरी कम रखने और स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया है,प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवस्था व्यावहारिक मानी जा सकती है, लेकिन इससे यह बहस भी शुरू हो गई है कि यदि यही मॉडल पहले अपनाया जा सकता था, तो वर्षों तक पूर्णकालिक संलग्नीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी?

कोरिया जिले में भी बढ़ी हलचल

एमसीबी के आदेश के बाद कोरिया जिले के शिक्षकों और छात्रावासों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच भी चर्चाएं तेज हो गई हैं,चर्चा है कि यदि कोरिया में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू होती है तो संकुल और निकटस्थ संकुल के शिक्षकों को छात्रावासों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।

वर्षों से छात्रावासों में जमे शिक्षकों का क्या होगा?

संलग्नीकरण समाप्ति की कार्रवाई के दौरान ऐसे कई शिक्षक मूल विद्यालयों में लौटे जो लंबे समय से छात्रावासों में कार्यरत थे,इनमें कुछ ऐसे भी थे जो पदोन्नति के बाद भी वर्षों तक विद्यालयों में नियमित रूप से नहीं लौटे थे,अब बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में छात्रावासों की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? क्या निकटस्थ विद्यालयों के शिक्षक ही यह जिम्मेदारी निभाएंगे या फिर पुराने अनुभव के आधार पर वही शिक्षक दोबारा व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे?

दोहरी जिम्मेदारी पर शिक्षक क्या सोचते हैं?

नई व्यवस्था में अतिरिक्त वेतन का कोई उल्लेख नहीं है,ऐसे में यह जानना भी महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षक इस व्यवस्था को किस नजर से देखते हैं,क्या इसे सेवा का अतिरिक्त दायित्व माना जा रहा है? क्या इससे विद्यालय और छात्रावास दोनों की व्यवस्था बेहतर होगी? या फिर शिक्षक संगठनों की ओर से इस पर कोई अलग राय सामने आएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही स्पष्ट होंगे।

छात्र सबसे महत्वपूर्ण कड़ी...

पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण पक्ष छात्र हैं,विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हों या छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी–दोनों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए,यदि नई व्यवस्था से दोनों संस्थानों का संचालन बेहतर होता है तो इसे सकारात्मक कदम माना जाएगा,लेकिन यदि किसी भी स्तर पर पढ़ाई,अनुशासन या छात्रावास प्रबंधन प्रभावित होता है तो प्रशासन को समय रहते समीक्षा करनी होगी।

शासन से अपेक्षा

एमसीबी जिले का यह आदेश अब पूरे सरगुजा संभाग में चर्चा का विषय है,शासन द्वारा संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्णय के बाद यह पहला बड़ा प्रशासनिक मॉडल सामने आया है, अब आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा विभाग और आदिम जाति विकास विभाग संयुक्त रूप से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें कि छात्रावासों में अधीक्षक की व्यवस्था किस प्रकार संचालित होगी,अतिरिक्त दायित्व की सीमा क्या होगी और यह व्यवस्था अस्थायी है या स्थायी, क्योंकि यदि हर जिले में अलग-अलग मॉडल अपनाए गए तो भविष्य में फिर वही भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है,जिसे समाप्त करने के लिए संलग्नीकरण खत्म करने का निर्णय लिया गया था,एमसीबी का आदेश फिलहाल इतना जरूर बता रहा है कि संलग्नीकरण की बहस समाप्त नहीं हुई है,उसका स्वरूप बदल गया है,और अब यह बहस इस बात पर केंद्रित है कि क्या अतिरिक्त दायित्व की यह व्यवस्था शासन की मूल मंशा के अनुरूप है या फिर प्रशासनिक आवश्यकता के तहत निकाला गया एक व्यावहारिक समाधान।

स्कूल गेम्स मलखंब में कोरिया का दमदार प्रदर्शन,5 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन

संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सुंदरपुर स्कूल के खिलाड़ियों ने लहराया परचम,जिला शिक्षा अधिकारी ने दी बधाई...

-संवाददाता-

अंबिकापुर/कोरिया,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तरीय स्कूल गेम्स मलखंब प्रतियोगिता में जिले का नाम रोशन किया है, अंबिकापुर के ऐतिहासिक गांधी स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुंदरपुर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल पांच खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन सुनिश्चित कराया, संभाग स्तर की इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला,इसके बावजूद कोरिया जिले के खिलाड़ियों ने संतुलन, तकनीकी कौशल और आत्मविश्वास का परिचय देते हुए निर्णायकों को प्रभावित किया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई।

सुंदरपुर स्कूल के खिलाड़ियों ने बढ़ाया जिले का गौरव-प्रतियोगिता में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सुंदरपुर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे उल्लेखनीय रहा,अलग-अलग आयु वर्ग में विद्यालय के पांच खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट

प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया,19 वर्ष आयु वर्ग में विद्यालय के आकाश राजवाड़े, अनिकेत राजवाड़े,गणेश राजवाड़े और आशीष ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर के लिए अपना चयन सुनिश्चित किया,वहीं 17 वर्ष आयु वर्ग में शिवशंकर राजवाड़े ने बेहतरीन प्रदर्शन कर संभागीय टीम में स्थान बनाया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का टिकट हासिल किया।

अब राज्य स्तर पर दिखाएंगे हुनर- संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने के बाद अब ये सभी खिलाड़ी राज्य स्तरीय स्कूल गेम्स मलखंब प्रतियोगिता में कोरिया जिले और सरगुजा संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे,खिलाड़ियों से जिले को पदक की उम्मीदें हैं और खेल प्रेमियों को विश्वास है कि वे राज्य स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।

कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का मिला परिणाम-खिलाड़ियों की इस उपलब्धि के पीछे उनकी निरंतर मेहनत और नियमित अभ्यास के साथ-साथ मलखंब प्रशिक्षक अमित शर्मा का विशेष योगदान माना जा रहा है,उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने तकनीकी दक्षता और आत्मविश्वास विकसित किया,जिसका परिणाम संभाग स्तर की प्रतियोगिता में देखने को मिला।

जिला शिक्षा अधिकारी ने दी शुभकामनाएं-इस उपलब्धि पर जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने सभी चयनित खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षक अमित शर्मा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की,उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की सफलता उनकी मेहनत,अनुशासन और प्रशिक्षक के समर्पित मार्गदर्शन का परिणाम है, उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी कोरिया जिले के खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले और संभाग का नाम रोशन करेंगे।

खिलाड़ियों ने जताया आभार

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों और प्रशिक्षक अमित शर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि उन्हें जो प्रोत्साहन और सहयोग मिला है, उसी के बल पर वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं,खिलाड़ियों ने राज्य स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन कर जिले के लिए पदक जीतने का संकल्प व्यक्त किया, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में मिली इस सफलता से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,सुंदरपुर के शिक्षकों,विद्यार्थियों, अभिभावकों और पूरे कोरिया जिले में खुशी का माहौल है,खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी जिले के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।

भाजपा जिला कोरिया की संगठ्नात्मक बैठक सम्पन्न, बूथ से शक्ति केंद्र तक संगठ्न मजबूत करने पर जोर

मंडलवार समीक्षा,आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तैयार,बैठकों में उपस्थिति को लेकर भी जारी हुए निर्देश

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया की आवश्यक संगठनात्मक बैठक सोमवार को जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारियों,मंडल प्रभारियों, मंडल अध्यक्षों तथा शक्ति केंद्र प्रभारियों ने भाग लिया,इस दौरान संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई।

बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने की, इस अवसर पर प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णबिहारी जायसवाल सहित जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे, बैठक में मंडलवार संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए बूथ समितियों के गठन, शक्ति केंद्र बैठकों की तैयारियों, मंडल स्तर पर विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के गठन तथा आगामी माह में आयोजित होने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई, बैठक में प्रदेश संगठन के निर्देशों की

जानकारी देते हुए निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मंडल की बैठक के बाद उपस्थित एवं अनुपस्थित पदाधिकारियों की जानकारी जिला कार्यालय को भेजी जाएगी, इसी प्रकार जिला स्तर की बैठकों में जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का विवरण भी प्रदेश कार्यालय को नियमित रूप से प्रेषित किया जाएगा, ताकि संगठनात्मक गतिविधियों की सतत समीक्षा हो सके, बैठक में शक्ति केंद्र बैठकों, प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन तथा बूथ समिति की नियमित बैठकों को सफल बनाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की गई, पार्टी पदाधिकारियों से कहा गया कि वे संगठन के कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें, इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, बसंत राय, अनिल साहू, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, जिला मंत्री शिवकुमारी सोनपाकर, जिला मीडिया प्रभारी तीरथ राजवाड़े, जिला कार्यालय मंत्री मंजू जीवनानी, सह कार्यालय मंत्री मनोज साहू, मंडल अध्यक्ष रामलखन यादव, दीपा विश्वकर्मा, किशोर सिरदार, संजय चिकनजूरी, राजाराम राजवाड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू, कुबेर साहू, जनपद सदस्य रंजीत मंडल, महामंत्री सत्यम साहू, सुरेश राजवाड़े, डॉ. भुवन साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

CMYK

'ग्राम सभा का प्रस्ताव मान्य, फिर 1946 का रिकॉर्ड क्यों?'

जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा पण्डो समाज

आयोग के निर्देश, कमिश्नर की रिपोर्ट और विभागीय आदेश के बावजूद नहीं मिल रही राहत

- ग्राम सभा के प्रस्ताव को मान्यता देने का निर्देश
- 'भुइंहार-परहिया' पण्डो की उपजाति
- लिपिकीय त्रुटि सुधारने के आदेश पहले से मौजूद
- भूमि माफियाओं के शोषण की भी जताई आशंका

कलेक्टर से की हस्तक्षेप की मांग
पण्डो जनजाति कल्याण समिति की गुहार

1946 के रिकॉर्ड की शर्त ने छीने सपने! पण्डो समाज के युवाओं का भविष्य अधर में

पण्डो समाज का सवाल-जब ग्राम सभा का प्रस्ताव मान्य है तो 80 साल पुराने दस्तावेज क्यों?

जाति प्रमाण पत्र के लिए 1946 का रिकॉर्ड! विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डो ने कलेक्टर से लगाई गुहार

कमिश्नर की रिपोर्ट में 'भुइंहार-परहिया' पण्डो की उपजाति,फिर भी प्रमाण पत्र पर अड़चन क्यों?

शासन के आदेश अलग,जमीनी हकीकत अलग! जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा पण्डो समाज

1946 के दस्तावेज नहीं,इसलिए नहीं मिल रहा अधिकार? पण्डो समाज ने उठाए प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल

जाति प्रमाण पत्र के अभाव में शिक्षा और नौकरी पर संकट,पण्डो समाज ने मांगा कलेक्टर का हस्तक्षेप

कागजों में उलझा पण्डो समाजः आयोग की गाइडलाइन के बावजूद जाति प्रमाण-पत्र के लिए लंबा इंतजार

-राजन पाण्डेय-

सोनहत/कोरिया,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) पण्डो समाज आज एक ऐसी प्रशासनिक उलझन में फंस गया है, जिसने समाज की नई पीढ़ी के भविष्य पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है, जिस जाति ने सदियों तक जंगलों और पहाड़ों के बीच प्रकृति के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, आज उसी समाज के युवाओं से 1946-47 के भूमि राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा रही है, ऐसे दस्तावेज, जो अधिकांश परिवारों के पास कभी थे ही नहीं, अब जाति प्रमाण पत्र का आधार बनाए जा रहे हैं, इस स्थिति ने सैकड़ों छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा,छात्रवृत्ति,प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों के रास्ते रोक दिए हैं,पण्डो जनजाति कल्याण समिति ने इसे केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए जिला कलेक्टर से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

नई पीढ़ी के सपनों पर लग गया विराम-जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने का सबसे अधिक असर विद्यार्थियों और युवाओं पर पड़ रहा है,समिति के अनुसार कई छात्र-छात्राएं कॉलेजों में अनुसूचित जनजाति कोटे का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, छात्रवृत्तियां रुक रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा और अनेक युवा सरकारी नौकरियों के आवेदन से ही वंचित हो रहे हैं,समाज का कहना है कि प्रशासनिक प्रक्रिया की जटिलता के कारण प्रतिभाशाली युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है।

जब आयोग ने ग्राम सभा के प्रस्ताव को पर्याप्त माना,फिर आपत्ति क्यों?- समिति ने अपने ज्ञापन में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वर्ष 2014 में जारी दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया है,आयोग की कंडिका-11 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास जाति सिद्ध करने के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं,तो ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को पर्याप्त आधार मानते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है,पण्डो समाज का आरोप है कि इस स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद कई मामलों में ग्राम सभा के प्रस्ताव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा और पुराने राजस्व अभिलेखों पर ही जोर दिया जा रहा है, समिति का सवाल है कि जब आयोग ने वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित कर दी है तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा।

पहले बने प्रमाण पत्र,अब क्यों बदले नियम?- पण्डो समाज के लोगों का कहना है कि पूर्व वर्षों में शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनेक लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, समिति का प्रश्न है कि यदि उसी प्रकार के मामलों में पहले प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते थे,तो अब उन्हीं परिस्थितियों में लोगों को क्यों भटकना पड़ रहा है? समाज ने प्रशासन से एक समान नीति अपनाने और सभी पात्र परिवारों को समान अवसर देने की मांग की है।

भूमि माफियाओं के सक्रिय होने की भी आशंका- समिति ने ज्ञापन में एक और गंभीर चिंता व्यक्त की है, उनका कहना है कि पुराने रिकॉर्ड की त्रुटियों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता का फायदा कुछ भूमि माफिया और बिचौलिए उठा रहे हैं,समिति का आरोप है कि सीधे-साधे आदिवासी परिवारों को भ्रमित कर उनकी भूमि और अधिकारों पर प्रभाव डालने की कोशिशें की जा रही हैं,यदि शासन के आदेशों का सही ढंग से पालन कराया जाए तो इस प्रकार के शोषण पर भी रोक लगाई जा सकती है।

कलेक्टर से की गई प्रमुख मांगें-पण्डो जनजाति कल्याण समिति ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि जिले के सभी एसडीएम (राजस्व) एवं तहसीलदारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं,आयोग,कमिश्नर कार्यालय और विभागीय आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए,जहां पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं,वहां ग्राम सभा के प्रस्ताव को पर्याप्त आधार माना जाए,लिपिकीय त्रुटियों और स्थानीय नामों के अंतर के कारण किसी पात्र व्यक्ति को वंचित न किया जाए,जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल,पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।

जाति प्रमाण पत्र बना सबसे बड़ी चुनौती

कोरिया जिले में पण्डो समाज के लोगों का कहना है कि आज सबसे बड़ी समस्या भोजन, आवास या रोजगार नहीं, बल्कि जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, बिना जाति प्रमाण पत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग को मिलने वाले अधिकांश संवैधानिक और शासकीय लाभ प्राप्त नहीं हो सकते, समिति के प्रदेश सह सचिव पवन साय पण्डो ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि वर्तमान में कई मामलों में राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 1946-47 के भूमि राजस्व अभिलेख मांगे जा रहे हैं, यह शर्त ऐसे समाज पर लागू की जा रही है, जिसके अधिकांश पूर्वज कभी राजस्व अभिलेखों में दर्ज ही नहीं हुए, समिति का कहना है कि यह प्रक्रिया न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि शासन की भावना के भी विपरीत है।

जंगलों में रहने वाले समाज से 80 साल पुराने दस्तावेज मांगना कितना न्यायसंगत?

पण्डो समाज छत्तीसगढ़ की उन विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है, जिनका पारंपरिक जीवन जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़ा रहा है, समाज के बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पूर्वजों के पास न तो भूमि के स्वामित्व संबंधी अभिलेख थे और न ही उस समय राजस्व रिकॉर्ड में उनका व्यवस्थित पंजीयन हुआ था, ऐसे में वर्तमान पीढ़ी से 1946-47 के दस्तावेज मांगना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। समिति का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर इसी कारण बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं और पात्र लोगों को भी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।

कमिश्नर की रिपोर्ट में भी मिल चुका है स्पष्ट आधार

ज्ञापन में सरगुजा संभाग के तत्कालीन आयुक्त कार्यालय द्वारा वर्ष 2022 में कराए गए विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान प्रतिवेदन का भी उल्लेख किया गया है, समिति के अनुसार इस अध्ययन में स्पष्ट कहा गया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज 'भुइंहार', 'परहिया' और 'पहारिया' अलग-अलग जातियां नहीं हैं, बल्कि पण्डो जनजाति के स्थानीय नाम अथवा उपजातियां हैं, समाज का कहना है कि कई बार पुराने दस्तावेजों में स्थानीय बोली के कारण अलग-अलग नाम दर्ज हो गए, लेकिन इससे मूल जनजातीय पहचान नहीं बदल जाती, इसलिए केवल नामों के अंतर के आधार पर किसी पात्र व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का लाभ देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

विभाग ने भी दिए थे त्रुटियां सुधारने के निर्देश

पण्डो समाज ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्ष 2022 में जारी आदेशों में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि पुराने राजस्व अभिलेखों में स्थानीय भाषा, लिपिकीय त्रुटियों अथवा नामों में अंतर के कारण उत्पन्न विवादों का समाधान करते हुए पात्र लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, समिति का कहना है कि यदि इन आदेशों का प्रभावी पालन हो तो अधिकांश विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका अपेक्षित पालन नहीं हो रहा।

प्रशासन के सामने परीक्षा, क्या मिलेगा समाधान?

पण्डो समाज का यह मुद्दा केवल एक प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं है,यह शिक्षा,रोजगार,सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न है, यदि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और विभागीय आदेशों का प्रभावी पालन होता है तो बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को राहत मिल सकती है,अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस विषय में क्या निर्णय लेता है और क्या विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को लंबे समय से चली आ रही इस समस्या से राहत मिल पाती है।

इनका कहना है...

'राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियों और पुराने कागजातों की अनुपलब्धता का अनुचित लाभ उठाकर भूमि माफिया और बिचौलिए सीधे-साधे आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। यदि शासन और कमिश्नर कार्यालय के निर्देशों का अक्षरशःपालन करते हुए एसडीएम (राजस्व) और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, तो पण्डो समाज को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सकती है। '

पवन साय पण्डो,प्रदेश सह सचिव,
पण्डो जनजाति कल्याण समिति

लज्या-अशोक कुमार अलंग स्मृति सम्मान समारोह का दसवां आयोजन 22 जुलाई को

बैकुंठपुर के दो शासकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों का होगा सम्मान,शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मिलेगा प्रोत्साहन

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लज्या-अशोक कुमार अलंग स्मृति सम्मान समारोह-2026 का आयोजन 22 जुलाई (बुधवार) को दोपहर 12 बजे से शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर में किया जाएगा,इस वर्ष यह सम्मान समारोह अपने दसवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

समारोह के अंतर्गत प्रतिवर्ष बैकुंठपुर के दो प्रमुख शासकीय विद्यालयों—शासकीय रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—के बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाता है, आयोजन प्रत्येक वर्ष एकांतर क्रम से दोनों विद्यालयों में आयोजित होता है। इस वर्ष सम्मान समारोह का आयोजन शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा, यह आयोजन वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं पूर्व कमिश्नर डॉ. संजय अलंग द्वारा अपने माता-पिता स्वर्गीय श्रीमती लज्या अलंग एवं स्वर्गीय श्री अशोक कुमार अलंग की स्मृति में कराया जाता है,स्वर्गीय श्रीमती लज्या अलंग ने शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैकुंठपुर में लंबे समय तक शिक्षकीय सेवाएं दीं,जबकि स्वर्गीय श्री अशोक कुमार अलंग ने शासकीय रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की,दोनों शिक्षकों ने अपने सेवाकाल में शिक्षा के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों के जीवन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण

योगदान दिया,डॉ. संजय अलंग की प्रारंभिक शिक्षा भी बैकुंठपुर में ही हुई,जिसके कारण उनका अपने गृह नगर और यहां की शैक्षणिक परंपरा से विशेष लगाव रहा है,इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने माता-पिता की स्मृति को शिक्षा और प्रतिभा सम्मान से जोड़ते हुए इस सम्मान समारोह की शुरुआत की, जो अब एक प्रेरणादायी परंपरा बन चुकी है,पिछले दस वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा यह समारोह न केवल मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करता है,बल्कि उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित भी करता है। साथ ही यह आयोजन समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने तथा समर्पित शिक्षकों के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन गया है,आयोजकों ने सभी शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों,सामाजिक कार्यकर्ताओं,गणमान्य नागरिकों एवं विद्यार्थियों से समारोह में उपस्थित होकर मेधावी छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन करने और शिक्षा के इस प्रेरणादायी आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की है।

शिवपुर-चरचा की जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन,सीएमओ को सौंपा मांगपत्र...

स्ट्रीट लाइट,पेयजल,नालियों की सफाई और अधूरे विकास कार्यों पर जताई नाराजगी,जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

-संवाददाता-

शिवपुर-चरचा/कोरिया,21 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा क्षेत्र में लगातार बनी हुई मूलभूत समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है,कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नगर के विभिन्न वार्डों की समस्याओं को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से मुलाकात कर विस्तृत मांगपत्र सौंपा,प्रतिनिधिमंडल ने नगर की बदहाल मूलभूत सुविधाओं पर चिंता जताते हुए शीघ्र समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समयबद्ध निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस परिवार जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

बंद स्ट्रीट लाइटों से बढ़ रही परेशानी-कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में बताया कि नगर के मुख्य मार्गों सहित कई वार्डों की स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं,रात के समय अंधेरा होने के कारण राहगीरों, महिलाओं और स्कूली विद्यार्थियों को आवागमन में भारी परेशानी होती है,साथ ही दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है,उन्होंने नगर पालिका से सभी बंद स्ट्रीट लाइटों को तत्काल चालू कराने की मांग की।

नालियों की सफाई और ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव की मांग-बरसात के मौसम को देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने नगर की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, उनका कहना था कि अधिकांश वार्डों की नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदगी और जलभराव की स्थिति बन रही है,

इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, उन्होंने सभी नालियों की नियमित सफाई कराने तथा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव सुनिश्चित करने की मांग की।

पार्क और प्रमुख चौकों की लाइटें भी हों चालू-प्रतिनिधिमंडल ने नगर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों की खराब प्रकाश व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया,उन्होंने महात्मा गांधी चौक,राजीव गांधी चौक,महंत जी पार्क, अटल जी पार्क सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर बंद पड़ी लाइटों को तत्काल दुरुस्त कराने की मांग की,नेताओं का कहना था कि सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त रोशनी नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक है।

टेंडर के बाद भी शुरू नहीं हुए विकास कार्य-कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर में कई विकास कार्यों के टेंडर जारी होने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए हैं,उन्होंने मांग की कि जिन कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें बिना देरी के शुरू कराया जाए ताकि नगरवासियों को विकास कार्यों का लाभ मिल सके।

पेयजल संकट का स्थायी समाधान हो-ज्ञापन में नगर की पेयजल व्यवस्था को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कई वार्डों में लोगों को नियमित पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, उन्होंने नगर पालिका से प्रतिदिन समय पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पानी की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की।

सीएमओ से की त्वरित कार्रवाई की मांग-प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से आग्रह किया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, ताकि नगरवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े, उन्होंने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ वातावरण, पर्याप्त रोशनी, पेयजल और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

समाधान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन

कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि नगर की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो कांग्रेस परिवार चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा, उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि नगरवासियों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए होगा।

ये रहे मौजूद

मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष लालमुनी यादव, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हेम सागर यादव, सोहेल अहमद (बल्ली मोदी), जागृत कुर्रे, विक्रांत सिंह, सोनू श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा, भूपेंद्र यादव, प्रीति किंडो, विजेंद्र कुमार, धर्मवीर यादव, जितेंद्र यादव, मोहम्मद सलीम अंसारी, एजाज गुड्डू, रामाधार, सोनू सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

फेदर ड्रेस में किसने बिखेरा ग्लैमर?

हिंदी मनोरजन उद्योग की जानी मानी हस्तियों में से दो है कैटरीना कैफ और अंकिता लोखंडे, जिन्हे दर्शको द्वारा खूब पसंद किया जाता है। दोनों ही अदाकारों का फैशन गेम बेहद शानदार और स्टाइलिश है, जिसके कारण उनके फैंस उनके आकर्षण के शिकार हो जाते हैं। हाल ही में, बड़े पर्दे पर धूम मचाने वाली कटरीना कैफ को फेदर ड्रेस में देखा गया था, जिसमें वह बेहद हसीन लग रही थी। जबकि टीवी की बहू अंकिता लोखंडे ने भी फेदर ड्रेस में कुदरती खूबसूरती दिखाई थी, जिसके कारण फैंस की नजरें उनसे हट नहीं रही है।

कैटरीना कैफ का फेदर लुक

मैरी क्रिसमस अभिनेत्री ने अपने फेदर लुक की बदौलत सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस लुक में वह बेहद हसीन लग रही थी और उन्होंने इसे अपने करोड़ों फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए शेयर किया है। अभिनेत्री ने एक काले रंग की सरासर बिना आस्तीन की गहरी गहरी नेकलाइन को बदन पर सजाया था, जिसके साथ नीले और सरसों के पीले पंख जैसे नजर आ रहे हैं। जबकि उन्होंने अपने बालों को मैसी बन हेयरस्टाइल में स्टाइल किया था। डीवा ने मैट आईशैडो, नीली और काली आईलाइनर, सफेद काजल, हाइलाइट किए हुए गाल और नाक की नोक के साथ झिलमिलाता मेकअप लगाया और इसे नग्न गुलाबी लिपस्टिक के साथ जोड़ा। उन्होंने अपने आउटफिट के साथ सिम्सम फाइन ज्वेलरी का सिल्वर चेन चोकर पहना है।

5 खिलाड़ी जिनका करियर गौतम गंभीर के आने के बाद हुआ खत्म! एक के नाम तो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट

नई दिल्ली,21 जुलाई 2026। जब से गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने हैं तभी से उथल पुथल मची हुई है। टीम को जहां कई बड़ी सीरीजों में हार का सामना करना पड़ा,वहीं कुछ खिलाड़ियों की गंभीर के साथ विवाद

की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। गंभीर के आने के बाद टीम इंडिया के कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनका करियर या तो खत्म हो गया या उनकी टीम में वापसी ही नहीं हो पा रही। ऐसे ही 5 खिलाडियों की बात हम आगे करने वाले हैं।

भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों में शुमार रोहित शर्मा को इस दौर में सबसे बड़ा झटका लगा है। युवाओं को आगे लाने और कप्तानी में बदलाव की नीति के तहत रोहित शर्मा को न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से दूर होना पड़ा बल्कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी भी छीन ली गई। शानदार फॉर्म में होने के बावजूद जिस तरह से रोहित को नेतृत्व पद से हटाया गया उसने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं रोहित को लगातार वनडे टीम से ड्रॉप करने की बात की जा रही है। आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज विराट कोहली को भी इस फेरबदल की गाज झेलनी पड़ी है। गौतम गंभीर के कार्यकाल में पूरी टीम के पुनर्गठन की योजना बनाई गई जिसके तहत कोहली को भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा।

क्या सोने के चक्कर में हीरा गंवा रही टीम इंडिया

नई दिल्ली,21 जुलाई 2026। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव के साथ हो रहे लगातार अनदेखे रवैये को लेकर विवाद गहरा गया है। इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज से आराम दिए जाने के बाद कुलदीप को वनडे सीरीज के तीनों ही मैचों में प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी फिरकी का लोहा मनवाने वाले इस मुख्य स्पिनर को एक बार फिर केवल बेंच गर्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

'द इंडिया स्टोरी' का एक और दमदार पोस्टर रिलीज़

कीटनाशक खेती की भयावह सच्चाई से उठाया पर्दा...

फिल्म 'द इंडिया स्टोरी' के निर्माताओं ने फिल्म का एक नया और प्रभावशाली पोस्टर जारी किया है, जो देश के सबसे गंभीर जनस्वास्थ्य मुद्दों में से एक कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल वाली खेती पर ध्यान केंद्रित करता है। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े अभिनीत यह नया पोस्टर फिल्म की दमदार कहानी की झलक देने के साथ-साथ कृषि में बढ़ते कीटनाशकों के इस्तेमाल से जुड़े उन खतरों को भी सामने लाता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चुपचाप प्रभावित कर रहे हैं।

नया पोस्टर बेहद प्रभावशाली विजुअल्स के साथ फिल्म के मूल संदेश को सामने रखता है। यह दर्शाता है कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला भोजन किन छिपे हुए खतरों को अपने साथ ला सकता है। पोस्टर का गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला अंदाज़ फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ाता है। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े इस कहानी के केंद्र में हैं, जो पीढ़ियों से जुड़ी एक अहम समस्या पर जागरूकता फैलाने का प्रयास करती है।

फिल्म के संदेश पर बात करते हुए काजल अग्रवाल ने कहा, 'द इंडिया स्टोरी' ऐसी फिल्म है, जो हर घर तक पहुंचने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस प्रोजेक्ट ने मुझे इसलिए आकर्षित किया, क्योंकि यह एक ऐसे विषय को उठाने का साहस करता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है,लेकिन अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है। मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म लोगों को अपने भोजन और उससे जुड़े विकल्पों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित करेगी।

वहीं श्रेयस तलपड़े ने कहा,यह कहानी सिर्फ खेती की पद्धतियों की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और भविष्य की भी है। नया पोस्टर उसी गंभीरता और तात्कालिकता को दर्शाता है, जिसे हम इस फिल्म के जरिए सामने लाना चाहते हैं। हम ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते थे,जो समाज में सार्थक चर्चा शुरू करे और मुझे विश्वास है कि 'द इंडिया स्टोरी' लोगों में इस विषय को लेकर जागरूकता पैदा करेगी।

'द इंडिया स्टोरी' पहले ही कीटनाशक खेती और उसके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों जैसे संवेदनशील विषय को उठाने के कारण चर्चा में है। फिल्म यह दिखाने का प्रयास करती है कि किस तरह हानिकारक कृषि पद्धतियां वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही यह दर्शकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि आखिर उनकी थाली तक पहुंचने वाला भोजन कितना सुरक्षित है। अपनी प्रभावशाली कहानी के माध्यम से फिल्म खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य जैसे अहम

मुद्दों पर सार्थक संवाद शुरू करने का प्रयास करती है।

ज़ी स्टूडियोज़ और एमआईजी प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज़ के सहयोग से प्रस्तुत 'द इंडिया स्टोरी' का निर्देशन चेतन डी.के. ने किया है, जबकि इसकी कहानी और निर्माण सागर बी. शिंदे ने किया है। फिल्म 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज़ होगी।

फिल्म के सह-निर्माताओं में स्वाति विनायक सैंदाने, अनीता जाधव, विनायक सैंदाने, कल्पेश शाह, देवयानी खोराटे और प्रेम जोशी शामिल हैं। तकनीकी टीम में सिनेमैटोग्राफर निशांत भागवत, संगीतकार मंगेश धाकड़े,एडिटर आशीष म्हात्रे, गीतकार शकील आज़मी और साउंड डिज़ाइनर अनमोल भावे शामिल हैं। अपने प्रासंगिक विषय और सशक्त संदेश के साथ 'द इंडिया स्टोरी' रिलीज़ से पहले लगातार चर्चा बटोर रही है।

बाहुबली की राजमाता का वो आइटम सॉन्ग

70 के दो सुपरस्टार्स संग किया रोमांस;आज भी कल्ट है ये सुपरहिट गाना

अगर आपने फिल्म बाहुबली देखी है,तो आपको उसमें राजमाता शिवगामी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस राम्या कृष्णन जरूर याद होंगी। हालांकि कई लोगों को लगता है कि राम्या कृष्णन ने हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। राम्या कृष्णन ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, यहां तक कि उनके कई आइटम सॉन्ग भी हैं, जो आज भी सुपरहिट हैं।

सुपरहिट है राम्या का आइटम सॉन्ग

अब यूं तो राम्या कृष्णनन ने अपने हिंदी फिल्मों के करियर में कई हिट गाने दिए और कई फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। हालांकि उनका एक गाना तो इतना पॉपुलर हुआ कि इस गाने का दोबारा रीमेक वर्जन तक बना है और उस गाने का नाम है चाहे मेरी जान तू ले ले।

जी हां, साल 1988 में आई फिल्म दयावान के इस गाने में उस दौर के सुपरस्टार्स फिरोज खान और विनोद खन्ना नजर आए थे। फिल्म के इस गाने में इन दोनों स्टार्स के साथ जो हीरोइन नजर आई है, वो कोई और नहीं बल्कि बाहुबली में माता शिवगामी का किरदार निभाने वाली मशहूर एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ही हैं।

साहिबा बाली ने आखिरकार अपनी डेटिंग से जुड़ी अफ़वाहों पर चुप्पी तोड़ी

एक्टर और कंटेंट क्रिएटर साहिबा बाली ने आखिरकार अपनी पर्सनल लाइफ़—खासकर अर्जुन कपूर के साथ रोमांटिक रिश्ते की अफ़वाहों—पर चुप्पी तोड़ी है। अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में, एक्ट्रेस ने मीडिया से कहा कि वे उनके रिश्तों और दोस्ती के बारे में अटकलें लगाना बंद करें; इसके बजाय, उन्हें लंदन में CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के प्रोटेस्ट को दिखाना चाहिए।

साहिबा बाली का बयान

साहिबा ने लंदन में इंडियन एम्बेसी की एक झलक शेयर की, जहाँ कई लोग प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा हुए थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की माँग कर रहे थे और बेहतर शिक्षा सुधार के लिए CJP के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। अपने कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा,डियर मीडिया, लंदन में मेरी डेटिंग लाइफ़/दोस्ती के बारे में अटकलें लगाना बंद करो—यह कोई नेशनल न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर दिखाना ही है तो यह दिखाओ ना).

साहिबा और अर्जुन की डेटिंग की अफ़वाहें रविवार को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारत बनाम इंग्लैंड ODI मैच के दौरान अर्जुन कपूर के साथ साहिबा की तस्वीरें वायरल होने के बाद वे चर्चा का केंद्र बन गईं, जिससे डेटिंग की अफ़वाहें शुरू हो गईं।

हालाँकि, अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट में एक्ट्रेस ने इन अफ़वाहों को अप्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने अर्जुन के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा,हर बात पर यकीन न करें।

वर्क फ्रंट

साहिबा एक एक्ट्रेस और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और उन्होंने मार्केटिंग के क्षेत्र में भी काम किया है। उन्होंने 2018 में 'लैला मजनू' से एक्टिंग की शुरुआत की,जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार की बहन की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा, वह 'अमर सिंह चमकीला', 'बार्ड ऑफ़ ब्लड' और अन्य प्रोजेक्ट्स में भी नज़र आ चुकी हैं।

अर्जेंटीना को चीटिंग से फाइनल में पहुंचा दिया,सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कर दी ऐसी हरकत,मच गया बवाल

नई दिल्ली,21 जुलाई 2026। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बीच सालों पुरानी प्रतिद्वंद्विता ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। रोनाल्डो के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ऐसे वायरल वीडियो को लाइक किया गया जिसमें विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा पर 2026 विश्व कप के दौरान अर्जेंटीना और मेसी को फायदा पहुंचाने के लिए धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

फाइनल में हारी थी अर्जेंटीना की टीम

भले ही यह एक सोशल मीडिया एक्शन था, लेकिन इसने फुटबॉल जगत में फीफा के खिलाफ भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों के मुद्दे को फिर से बाहर निकाल दिया है। गौरतलब है कि उत्तरी अमेरिका (अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको) में खेले गए 2026 के विश्व कप में रोनाल्डो और पुर्तगाल का सफर जल्दी खत्म हो गया था जबकि मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की टीम फाइनल तक पहुंची थी,जहां उन्हें अतिरिक्त समय में स्पेन के हाथों 0-1 से हार का सामना करना पड़ा।

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था वीडियो

इस टूर्नामेंट के बाद एक वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से फैला जिसमें आरोप लगाया गया कि मैच रेफरी और वीएआर के कई संदिग्ध फैसलों ने लगातार अर्जेंटीना का पक्ष लिया, जिससे मेसी की टीम को फाइनल का टिकट आसानी से मिल सका। रोनाल्डो के वेरिफाइड अकाउंट द्वारा इस वीडियो को लाइक किए जाने के स्क्रीनशॉट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए फैंस के बीच बहस छिड़ गई।

सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करने पर बवाल

रोनाल्डो ने इस पर खुद कोई टिप्पणी या आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन उनके फैंस का मानना है कि यह फीफा द्वारा मेसी को बढ़ावा देने की नीति पर रोनाल्डो का मौन विरोध है। हालांकि,यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि सोशल मीडिया पर केवल एक लाइक किसी भ्रष्टाचार या मैच फिक्सिंग का कानूनी सबूत नहीं है और फीफा द्वारा मेसी के लिए धोखाधड़ी करने के इन दावों की किसी भी आधिकारिक संस्था ने पुष्टि नहीं की है।

कप्तानी मिलते ही चल गया बल्ला, बाबर आजम ने ठोका जबरदस्त शतक

नई दिल्ली,21 जुलाई 2026। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टेस्ट कप्तानी की जिम्मेदारी दोबारा संभालने के तुरंत बाद जबरदस्त शतक ठोका है। वेस्टइंडीज 11 के खिलाफ अभ्यास मैच की पहली पारी में पाकिस्तान ने 136.5 ओवरों में 455 रन बनाकर 4 विकेट के नुकसान पर अपनी पारी घोषित की। कुछ ही समय पहले बाबर से टीम की कप्तानी छीनी गई थी, लेकिन टेस्ट में बतौर कप्तान लौटते ही उन्होंने फॉर्म में भी वापसी कर ली है।

बाबर आजम ने ठोका शतक

कप्तान बाबर आजम ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट्स लगाए। उन्होंने 151 गेंदों का सामना करते हुए ठीक 100 रनों की धैर्यपूर्ण और प्रभावशाली पारी खेली। अपनी इस पारी में बाबर ने 12 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। शतक पूरा करने के बाद वे रिटायर हर्ट होकर पवेलियन लौटे, जिससे अन्य बल्लेबाजों को खेलने का मौका मिल सके।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विश्वनाथ आ.स्व. जंगसाय. जाति-(छिपीदर्जी) निवासी सत्तीपारा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक के पिता जंगसाय आ.स्व. सुईलाराम के स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लॉट नंबर 3221 रकबा 0.02 ऐकड़ भूमि है। भूधारक जंगसाय आ.स्व. सुईलाराम की मृत्यु दिनांक 12.06.2004 को हो गई है। तत्पश्चात आवेदित भूमि से जंगसाय का नाम विलोपित कर स्वयं के नाम से फौति नामांतरण किये जाने हेतु आवेदक द्वारा अपने जंगसाय के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति गय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 27, 07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 10/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सील) **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सरस्वती सोनी पति अन्तु कुमार सोनी, निवासी सत्तीपारा नेहरूवार्ड अम्बिकापुर, तह0 अ0पुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदिका के ससुर बृजबिहारी प्रसाद आ0 स्व. परमेश्वर के द्वारा स्वयं के स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अ0पुर मोहल्ला सत्तीपारा स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 636/13 रकबा 800 वर्गफीट भूमि का पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 01.06.2016 का निष्पादन आवेदिका के पक्ष में किया गया है। भूधारक बृजबिहारी प्रसाद सोनी की मृत्यु दिनांक 17.12.2020 को हो गई है। अतः उक्त पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 01.06.2016 के आधार पर आवेदिका द्वारा वसीयतशुदा भूमि का नामांतरण स्वयं के नाम से किये जाने हेतु पंजीबद्ध वसीयतनामा की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 06/08/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 21/07/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंवं हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सील) **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नायब तहसीलदार
अम्बिकापुर-3,जिला-सरगुजा,छग0

रा0प्र0क्र0 202603022900007 /अ-27/2025-26

फर्द बटवारा का अंतिम प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 रा0प्र0क्र0 202603022900007/अ-27/2025-26 पक्षकार रामकुमार सांडिल्य प्रति सुमित्रा वगै0 में ग्राम नवागढ़ स्थित खसरा नम्बर 189/1 रकबा 0.138 हे0 भूमि का बंटवारा हेतु फर्द बंटवारा सूची हल्का पटवारी से प्राप्त हुआ है, जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त फर्द बंटवारा में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30/07/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 16/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) **नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3**

न्यायालय नायब तहसीलदार
अम्बिकापुर-3,जिला-सरगुजा,छग0

रा0प्र0क्र0 202603022900006 /अ-27/2025-26

फर्द बटवारा का अंतिम प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के रा0प्र0क्र0 रा0प्र0क्र0 202603022900006/अ-27/2025-26 पक्षकार रामकुमार सांडिल्य प्रति सुमित्रा वगै0 में ग्राम नवागढ़ स्थित खसरा नम्बर 188/1 रकबा 1.147 हे0 भूमि का बंटवारा हेतु फर्द बंटवारा सूची हल्का पटवारी से प्राप्त हुआ है, जिसका अंतिम प्रकाशन कराया जा रहा है। अतः उक्त फर्द बंटवारा में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 30/07/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 16/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) **नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3**

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा0) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल,मनेन्द्रगढ़ (छ0ग0)

नीलाम-सूचना

सर्व सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि मनेन्द्रगढ़ मनमंडल के अधीनस्थ काष्ठागार जनकपुर में उपलब्ध नया पुराना ईमारती काष्ठ एवं जलाऊ काष्ठ का दर्शित तिथि व समय में ई-ऑक्सन द्वारा निवर्तन किया जाना है, इच्छुक व्यापारी ई-ऑक्सन मे अवश्य भाग लेवे। ई-ऑक्शन की शर्ते एवं अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस व समय पर वनमण्डल कार्यालय अथवा काष्ठागार जनकपुर से प्राप्त कर सकते है।

डिपों का नाम- काष्ठागार जनकपुर
नीलाम दिनांक- 31.07.2026
नीलाम प्रारंभ - प्रातः 9.00 बजे से प्रारम्भ

क्र	प्रजाति	नये अविक्रित काष्ठ		पुराने अविक्रित काष्ठ			
		लण्ठा	बल्ली	लण्ठा		बल्ली	
		घ0मी0	नग	नग	घ0मी0	नग	घ0मी0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सागौन	0.000	0	235	14.787	3652	39.364
2	साल	180.00	200	10861	1258.474	1350	42.422
3	साजा	0.250	0	15	1.275	1	0.022
4	धावड़ा	0.000	0	11	0.960	1	0.017
5	हल्दू,मुण्डी,बांसा	0.000	0	2	0.087	1	0.00
6	नीलगिरी	0.000	0	0	0.000	560	2.993
	योगः=	**180.250**	**200**	**11124**	**1275.583**	**5564**	**84.821**
7	मिश्रीत जलाऊ	-		80 चट्टा पुराना			
योग :-		200 चट्टा नया		80 चट्टा पुराना			

टीपः- 1. केता को ई-ऑक्सन के पूर्व MSTC E-commerce पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है ।
2. केताओं को ई-ऑक्शन के पूर्व कय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है, सफल बोलीदार को एक सप्ताह के भीतर 15 प्रतिशत E.M.D. की राशि जमा करना अनिवार्य है।
3. लॉट की थम्पी एवं फोटो MSTC E-commerce पोर्टल में अपने आई.डी से लॉगईन करके देख सकते है।

जी.नं.-262702230/2

वनमंडलाधिकारी
मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल मनेन्द्रगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

मैं बच्चेलाल (पुराना नाम जिसे बदला जाना है) पिता स्व. देवराज, उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी ग्राम नवापारा, पोस्ट बंजा, पुलिस चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर, तहसील भैयाथान, जिला- सूरजपुर (छ.ग.) का स्थायी निवासी हूँ। मेरा पुराना नाम बच्चे लाल है और मैं अपना नाम बदलकर बच्चालाल (नया नाम) करवाना चाहता हूँ। मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में ऋण की राशि शेष है।

मैं नाम बदलकर यदि कोई गैर कानूनी काम करता हूँ तो उसके लिये मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। मैं यह शपथपत्र अपने पूरे होशो हवास में रहकर हस्ताक्षर कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है।

शपथग्रहिता
बच्चालाल

रायपुर लोकभवन के बाहर कांग्रेसियों का धरना

कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की....

रायपुर,21 जुलाई 2026। दिल्ली में पीएम आवास के बाहर मंगलवार दोपहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि, प्रधानमंत्री आवास के बाहर से पुलिस ने हमारे सीनियर नेताओं के साथ मुझे भी बस में बैठा लिया है। एयरपोर्ट की तरफ कहीं लेकर जा रहे। दिल्ली पुलिस ने मेरा एक जूता भी ले लिया है।

इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी के समर्थन में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी लोकभवन के पास प्रदर्शन किया। विरोध करने पहुंचे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने लोकभवन के गेट तक बढ़ने की

कोशिश की,जिसके बाद वहां धक्का-मुक्की और अफरातफरी का माहौल बन गया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और शिक्षा सुधारों को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है।

कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भजन-कीर्तन किया,सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लोकभवन के गेट तक बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद वहां धक्का-मुक्की और अफरातफरी का माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

जब तक न्याय नहीं,तब तक विरोध जारी

पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने कहा...कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। बच्चों पर लाठीचार्ज हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता ने शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं,कांग्रेस नेता सुबोध हरितवाल ने कहा, जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा,हम विरोध करते रहेंगे।

बाल संप्रेषण गृह में चौकीदार की हत्या करने वाले तीन आरोपी अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार,चौथे की तलाश जारी

बिलासपुर,21 जुलाई 2026। सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित बाल संप्रेषण गृह में चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। फरार चार आरोपियों में से तीन को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथे आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक,हत्या के बाद आरोपी अलग-अलग राज्यों में छिप गए थे ताकि पुलिस की पकड़ से बच सकें। सबसे पहले दिनेश राठिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को पटना और बेंगलुरु से भी गिरफ्तार कर लिया। अब एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश कई राज्यों में जारी है।

हाथ-पैर बांधकर की थी हत्या

जांच में सामने आया है कि चारों आरोपियों ने पहले चौकीदार नरेंद्र कुमार खांडे के साथ मारपीट की। इसके बाद उनके हाथ-पैर बांध दिए, गला दबाया और मुंह में गमछा ठूंस दिया,जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे।

बालिग होने के बाद सेफ्टी यूनिट में थे आरोपी

पुलिस के अनुसार,आरोपियों ने अपने पुराने अपराध किशोर अवस्था में किए थे। हालांकि,इस हत्याकांड के समय सभी आरोपी बालिग हो चुके थे। इसी कारण उन्हें बाल संप्रेषण गृह की प्ले सेफ सेफ्टी यूनिट में रखा गया था।

चौथे आरोपी की तलाश जारी

पुलिस की विशेष टीमें फरार चौथे आरोपी की तलाश में लगातार विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा न्यायालय के समक्ष किया जाएगा।

किन्नर की हत्या से फैली सनसनी...गला दबाकर उतारा मौत के घाट,सड़क किनारे मिला शव

बिलासपुर,21 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक किन्नर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सकरी थाना क्षेत्र के जोंकी गांव में सड़क किनारे एक किन्नर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान तनु खान किन्नर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार,किन्नर के साथ पहले मारपीट की गई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को सड़क किनारे फेंक दिया। सुबह शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मामले में शुरुआती तौर पर साथी किन्नरों पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की असली वजह और इसमें शामिल आरोपियों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। सूचना मिलते ही सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही हत्या से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

दुर्ग में चरागाह जमीन पर बायोगैस प्लांट का विरोध...कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण,कांग्रेस बोली- निर्माण नहीं रुका तो करेंगे बड़ा आंदोलन

दुर्ग-भिलाई,21 जुलाई 2026। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत खेरथा में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बायोगैस प्लांट के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर प्लांट बनाया जा रहा है, उसका लंबे समय से गांव और आसपास के क्षेत्रों के पशुओं के चरागाह के रूप में उपयोग होता रहा है। ऐसे में यहां प्लांट बनने से पशुपालकों के सामने चारे और चराई की गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चरागाह की जमीन खत्म होने से पशुओं के लिए चारा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि इस मामले में ग्राम सभा और पंचायत की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि तहसीलदार ने ग्राम सभा और पंचायत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जो पेशा एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की सहमति के बिना इस तरह की परियोजना शुरू करना उचित नहीं है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि प्लांट शुरू होने के बाद आसपास के गांवों में दुर्गंध फैल सकती है। साथ ही प्रदूषण बढ़ने, भूजल प्रभावित होने और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किए बिना निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

राकेश ठाकुर बोले...कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग (ग्रामीण) के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों, ग्रामीणों और आम लोगों के हित की लड़ाई लड़ती रही है। यदि प्रशासन ग्रामीणों की मांगों को अनदेखा करता है और एकतरफा फैसला लेता है तो कांग्रेस ग्रामीणों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करेगी।

शव पहुंचते ही एक्टिव हो जाता था गैंग,सूचना लीक करने वाले 2 आरक्षक गिरफ्तार...

बिलासपुर,21 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के चर्चित फर्जी स्नेक बाइट मुआवजा घोटाले में पुलिस जांच के दौरान लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में सिम्स पुलिस चौकी के दो आरक्षक रामकुमार पाटनवार और रामेश्वर भास्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों अस्पताल में शव पहुंचते ही गिरोह को सूचना देते थे,जिसके बाद पूरा नेटवर्क सक्रिय हो जाता था। इस कार्रवाई के साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है।

अस्पताल से तहसील तक फैला था पूरा नेटवर्क : पुलिस जांच के अनुसार, सिम्स अस्पताल, पुलिस,तहसील कार्यालय और बिचौलियों का एक संगठित नेटवर्क फर्जी मुआवजा दिलाने का खेल चला रहा था। अस्पताल में शव पहुंचते ही पुलिसकर्मी गिरोह के सदस्य महेंद्र मनहर को सूचना देते थे। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य मृतक के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सरकारी मुआवजा दिलाने का लालच देते थे।

सामान्य मौत को बना देते थे 'सर्पदंश' : जांच में सामने आया कि बीमारी, कैंसर, आत्महत्या या अन्य कारणों से हुई मौतों को दस्तावेजों में सांप के काटने से हुई मौत दिखाया जाता था। फर्जी पंचनामा,पोस्टमार्टम रिपोर्ट और राजस्व दस्तावेज तैयार कर सरकार से आपदा राहत के रूप में मिलने वाली राशि का दावा किया जाता था। मुआवजे का कुछ हिस्सा परिजनों को देकर बाकी रकम गिरोह आपस में बांट लेता था।

अब तक 19 गिरफ्तार,कई विभागों के कर्मचारी शामिल : इस मामले में अब तक डॉक्टर,वकील,पुलिसकर्मी,राजस्व विभाग के कर्मचारी और बिचौलियों सहित 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई है,जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

लिपिक संघ ने जताया विरोध

राजस्व विभाग के तीन लिपिकों की गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सर्पदंश से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय राजस्व अधिकारियों का होता है,इसलिए केवल लिपिकों पर कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच की मांग की है।

विधानसभा में उठा था 17 करोड़ का मामला

यह घोटाला उस समय सुर्खियों में आया जब विधानसभा के मानसून सत्र में खुलासा हुआ कि जशपुर में तीन वर्षों में 96 सर्पदंश मौतें दर्ज हुईं, जबकि अकेले बिलासपुर में 431 मौतें दिखाकर करीब 17.24 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे,जिसके बाद लगातार गिरफ्तारियां और नए खुलासे सामने आ रहे हैं।

एम्स रायपुर में बड़ी सुविधा : ओपीडी मरीजों के लिए लैब टेस्ट हुआ पेपरलेस,अब बिना प्रिंटेड पर्ची सीधे होगा सैंपल कलेक्शन

रायपुर,21 जुलाई 2026। एम्स रायपुर ने ओपीडी मरीजों के लिए लैब जांच प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए पेपरलेस लैब टेस्ट रिक्विजिशन सिस्टम शुरू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब मरीजों को लैब जांच के लिए डॉक्टर की प्रिंटेड पर्ची लेकर अलग-अलग काउंटरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर जैसे ही जांच लिखेंगे,उसकी जानकारी सीधे प्रयोगशाला सूचना प्रणाली में दर्ज हो जाएगी। इसके साथ ही एम्स ने डोम-1 स्थित फलेबोटोमी (रक्त नमूना संग्रह) जोन को भी दोबारा शुरू कर दिया है। यहां मरीज सीधे पहुंचकर अपना पंजीकरण कराएंगे और सिस्टम में उपलब्ध जानकारी के आधार पर बारकोड तैयार होने के बाद रक्त या अन्य नमूनों का संग्रह किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कागजी प्रक्रिया लगभग समाप्त हो जाएगी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे मरीजों का इंतजार कम होगा, जांच पर्ची खोने

की समस्या खत्म होगी और सैंपल कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और व्यवस्थित होगी। डोम-1 फलेबोटोमी जोन में केंद्रीय वातानुकूलन सहित अन्य सुविधाओं का उन्नयन किया गया है। बच्चों के लिए अलग चाइल्ड-फ्रेंडली सैंपल कलेक्शन रूम बनाया गया है,जहां ऑडियो-वीडियो सुविधा उपलब्ध रहेगी ताकि रक्त नमूना देते समय बच्चों का तनाव कम किया जा सके। अस्पताल प्रशासन के अनुसार फलेबोटोमी से जुड़ी सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से डोम-1 स्थित नए जोन से संचालित होंगी। जिन ओपीडी मरीजों को लैब जांच करानी होगी।

पूरी निष्ठा और सेवा भाव से करें जनसेवा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में निभाएं महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,21 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ से अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनसे जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित होना केवल अभ्यर्थियों और उनके परिवार की नहीं,बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा समाज और राष्ट्र के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा इसमें कार्य करने वाले अधिकारियों को संवेदनशीलता,ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि उन्हें लोगों की सेवा का जो अवसर मिला है, वह ईश्वर का आशीर्वाद और समाज का विश्वास है। इस अवसर का उपयोग आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के

संकल्प को साकार करने में युवा प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता और सेवा भावना से छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस अवसर पर चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए तथा उनके मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया।

3 साल बाद कानून के शिकंजे में सहारा घोटाले का ब्रांच मैनेजर,40.78 करोड़ निवेश ठगी में बड़ी गिरफ्तारी

रायगढ़,21 जुलाई 2026। रायगढ़ पुलिस ने 'ऑपरेशन क्लीन हंट' के तहत सहारा इंडिया निवेश घोटाले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब तीन वर्षों से फरार चल रहे ब्रांच मैनेजर विजय कुमार शराफ को कोतरारोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार जिले सहित अन्य स्थानों के 3,848 निवेशकों से ?40.78 करोड़ से अधिक की कथित धोखाधड़ी की जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

वर्ष 2022 में रायगढ़ निवासी विकास निगानिया की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि वर्ष 2017 के दौरान सहारा इंडिया की विभिन्न निवेश योजनाओं में बेहतर रिटर्न और भरोसे का दावा कर शिकायतकर्ता तथा उसके परिवार सहित बड़ी संख्या में लोगों से रकम जमा कराई गई। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। जांच में सामने आया कि निवेशकों से ली गई राशि के बदले अलग-अलग सहकारी समितियों के नाम पर बॉण्ड जारी कर सुनियोजित तरीके से आर्थिक छल किया गया। विवेचना के दौरान प्रशासन,बैंकिंग संस्थानों,मंत्रालयों और निवेशकों से प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिसमें कंपनी के कई जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका सामने आई। पुलिस पहले ही कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कार्रवाई के

दौरान आरोपी से कंपनी से जुड़े प्रशासनिक दस्तावेज,एमओयू की प्रतियां तथा अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख जब्त किए गए। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल, एएसआई विल्फ्रेड मसीह और टीम ने मुखबिर सूचना के आधार पर दबिश देकर गिरफ्तारी की। मामले में फरार अन्य लोगों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय कुमार शराफ (54 वर्ष), निवासी विकास नगर, कोतरारोड़, रायगढ़ के रूप में हुई है,जो सहारा इंडिया के कबीर चौक स्थित शाखा का ब्रांच मैनेजर रहा है,गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। फिलहाल, रायगढ़ पुलिस का कहना है कि आर्थिक अपराध से जुड़े इस प्रकरण में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। नए साक्ष्य मिलने पर अन्य फरार आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि निवेशकों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया मजबूत हो सके।

बसों से नशा तस्करी रोकने बड़ा अभियान,पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश

रायपुर,21 जुलाई 2026। रायपुर पुलिस ने कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर विशेष निगरानी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। खासतौर पर बसों के माध्यम से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने नई रणनीति बनाई है। इसी क्रम में क्राइम एंड साइबर सेल की ओर से बस संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक क्राइम एंड साइबर डीसीपी के निर्देश पर आयोजित हुई,जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और परिवहन क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई।

बस संचालकों को दिए गए अहम सुरक्षा निर्देश : सिविल लाइन स्थित सी-4 भवन में आयोजित बैठक में पुलिस अधिकारियों ने बस संचालकों को कई आवश्यक निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अपराधी और तस्कर भी कर सकते हैं, इसलिए सभी संचालकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, व्यक्ति या सामान की जानकारी तुरंत संबंधित थाना, पुलिस कंट्रोल रूम या एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट को दी जानी चाहिए ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन होगा अनिवार्य : बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम एंड साइबर) गौरव मंडल ने बस संचालकों को निर्देश दिया कि उनके यहां कार्यरत सभी चालक, परिचालक, क्लीनर और अन्य कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही कर्मचारियों के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,मोबाइल नंबर,स्थायी एवं वर्तमान पता,फोटोग्राफ तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों का अद्यतन रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना सत्यापन किसी नए कर्मचारी को काम पर नियुक्त न किया जाए।

मादक पदार्थों की तस्करी पर रहेगी कड़ी नजर : पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की तस्करी रोकना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बसों के माध्यम से किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थों का परिवहन न हो,इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। यदि किसी यात्री, पार्सल या अन्य माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की आशंका होती है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को देना आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संदिग्ध पार्सल और लावारिस सामान से रहें सावधान

बैठक में बस संचालकों को यह भी निर्देश दिया गया कि बिना नाम,पहचान या वैध पते वाले व्यक्तियों के पार्सल स्वीकार न किए जाएं। प्रत्येक पार्सल का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए और किसी भी संदिग्ध पार्सल की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। पुलिस ने यह भी सलाह दी कि यदि बस में कोई लावारिस बैग, संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक जैसी सामग्री दिखाई दे तो उसे स्वयं खोलने या छूने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना देना सबसे सुरक्षित कदम होगा।

यात्रियों की पहचान और निगरानी पर विशेष जोर

पुलिस ने बस संचालकों से कहा कि यात्रा करने वाले यात्रियों का आवश्यक विवरण दर्ज किया जाए। बिना उचित पहचान या संदिग्ध दस्तावेज वाले व्यक्तियों को यात्रा कराने से बचने की सलाह दी गई है। यदि यात्रा के दौरान कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता हुआ दिखाई दे या उसके पास संदिग्ध सामग्री होने की आशंका हो, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही बस स्टैंड और बसों में लगे सीसीटीवी कैमरों को हमेशा सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। बस संचालकों ने पुलिस के निर्देशों का पालन करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा जताया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)